RNI No. DELMUL/2012/47011

23 जुलाई, 2026 गुरूवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 112

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देने तैयार है जिम्बाब्वे : सिकंदर रजा 07

संक्षिप्त वार्ता

30 लोकल ट्रेनें कैंसिल, कई एक्सप्रेस 5 घंटे लेट

नई दिल्ली। साहिबाबाद के पास मंगलवार को मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण दूसरे दिन भी ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। बुधवार को लंबी दूरी की कई ट्रेनें तीन से पांच घंटे की देरी से दिल्ली के स्टेशनों पर पहुंची। वहीं, 30 लोकल ट्रेनें निरस्त कर दी गई है जिससे दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

रिजिजू बोले सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बुधवार को भी जारी रहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सौ प्रतिशत तैयार है, लेकिन आरोप लगाया कि कांग्रेस बहाने बनाकर सदन की कार्यवाही बाधित कर रही है और चर्चा से बचना चाहती है।

दरअसल राज्यसभा में कार्यवाही दो बार स्थगित होने के बाद दोपहर दो बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सरकार की ओर से वक्तव्य देने के लिए किरेन रिजिजू को आमंत्रित किया। रिजिजू के बोलना शुरू करते ही विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की।

दल-बदल कानून की व्याख्या पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल रोधी कानून) की व्याख्या पर पुनर्विचार की मांग करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की याचिका को 27 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। याचिका में विशेष रूप से दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद-4 के तहत राजनीतिक दलों के विलय संबंधी प्रावधानों की व्याख्या स्पष्ट करने का आग्रह किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं, के समक्ष सिब्बल ने कहा कि उन्होंने यह याचिका व्यक्तिगत क्षमता में दायर की है और इसे शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

18 राज्यों में बारिश का अलर्ट

गुजरात-महाराष्ट्र में रेड अलर्ट

वेब वार्ता, नई दिल्ली

देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 23 जुलाई को देश के 18 राज्यों में हल्की से लेकर बेहद भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जा सकती है, जबकि कुछ राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन से चार दिनों तक मानसूनी गतिविधियां तेज बनी रहेंगी. कई इलाकों में जलभराव, बाढ़, भूस्खलन और तेज हवाओं जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है.

राजस्थान, मध्य प्रदेश और कोंकण-गोवा में भी भारी बारिश की चेतावनी

पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और कोंकण-गोवा के कई हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. लगातार बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और कई मार्गों के बाधित होने का खतरा बना हुआ है.

दिल्ली-एनसीआर को मिलेगी गर्मी से राहत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार को बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर तेज बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं. बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलेगी, लेकिन ऑफिस के समय ट्रैफिक जाम और जलभराव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

उत्तर प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज

उत्तर प्रदेश में मानसून धीरे-धीरे सक्रिय होता दिखाई दे रहा है. पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 जुलाई के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर और तेज हो सकता है. फिलहाल अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है.

गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में लगातार तेज बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों के पास न जाने और मौसम संबंधी ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है.

असम में बाढ़ से 21 लोगों की मौत, कई गांव डूबे, 5.64 लाख लोग प्रभावित

वेब वार्ता, गुवाहाटी

असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटों में 21 और लोगों की मौत हो गई, जबकि राज्य के 16 जिलों में 5.64 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। यह जानकारी एएसडीएमए ने देर रात जारी बुलेटिन में दी। बुलेटिन के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित शिवसागर जिले में 13 लोगों की मौत हुई है। चराइदेव में पांच, गोलाघाट में दो और जोरहाट में एक व्यक्ति की जान गई। इसके साथ ही इस साल राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। सीएम हिमंत विश्वा सरमा ने कहा कि वह बुधवार से बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट में एएसडीएमए के हवाले से बताया गया है कि बाढ़ से गोलाघाट, कामरूप, होजाई, डिब्रूगढ़, बिश्वनाथ, धेमाजी, सोनितपुर, उदालगुड़ी, नगांव, चराइदेव, कामरूप (मेट्रो), जोरहाट, तिनसुकिया, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर और शिवसागर सहित 16 जिलों में 5,64,600 से अधिक लोग प्रभावित हैं। सोमवार को 15 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या 3.63 लाख से ज्यादा थी। बुलेटिन के मुताबिक 44 राजस्व मंडलों के 872 गांव अब भी जलमग्न हैं। सबसे ज्यादा 3,59,535 लोग शिवसागर जिले में प्रभावित हैं।

लाठीचार्ज और बारिश के बावजूद जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी

वेब वार्ता, नई दिल्ली। शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन पुलिस कार्रवाई के बाद भी थमता नजर नहीं आया। सोमवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प तथा लाठीचार्ज में कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान आंदोलन का मंच क्षतिग्रस्त कर दिया गया और बिजली आपूर्ति भी बाधित कर दी गई। इसके बावजूद देर शाम से छात्र दोबारा बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पहुंचे और पूरी रात धरना-प्रदर्शन जारी रखा।

दिन में हुई पुलिस कार्रवाई के बाद कई घायल छात्रों को राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद कई छात्र वापस आंदोलन स्थल पर लौट आए और फिर से प्रदर्शन में शामिल हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें हटाने के लिए पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने लाठी-डंडों का इस्तेमाल किया, जिससे कई छात्रों के सिर और शरीर पर चोटें आईं। वहीं पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की सूचना है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, लाठीचार्ज के बाद जंतर-मंतर पर बना मंच क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि धरना स्थल पूरी तरह खाली नहीं कराया गया, जिसके चलते शाम ढलते ही छात्रों की संख्या फिर बढ़ने लगी। एहतियात के तौर पर पुलिस ने केरल भवन के पास बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही सीमित कर दी, लेकिन रात नौ बजे के बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ फिर बढ़ गई।

बड़ी संख्या में मौजूद रहे छात्र

रात करीब 10 बजे तेज बारिश और बिजली गुल होने से आंदोलनकारियों की मुश्किलें और बढ़ गईं। अंधेरे के बीच छात्रों ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाकर नारेबाजी जारी रखी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बारिश में बैठे प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अडिग रहे। देर रात तक आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे।

भोपाल बीजेपी ने किया कांग्रेस का घेराव

वेब वार्ता, भोपाल। दिल्ली में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास के घेराव के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को भोपाल में एक आक्रामक और जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ-साथ विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सबनानी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने किया।

विरोध जताने के लिए इन सभी नेताओं ने काले कपड़े पहनकर कांग्रेस पार्टी की रणनीति के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान जहां बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में इस विरोध प्रदर्शन के तौर-तरीकों और वहां सामने आए घटनाक्रम को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी का आक्रामक चेहरा दिखा वही कांग्रेस बीजेपी के स्वागत में गुलाब का गुलदस्ता लेकर नई रणनीति के साथ नजर आई । कांग्रेस की आक्रामक नीतियों के जवाब में बीजेपी अब सड़क पर उतरकर पूरी ताकत से मोचाबंदी करने में जुट गई है।

भारी बारिश से सड़क पर गिरे पत्थर-बोल्डर

केदारनाथ यात्रा को रोकना पड़ा, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया

वेब वार्ता, रुद्रप्रयाग

भारी बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर देखने को मिला है। गौरीकुण्ड से करीब एक किलोमीटर आगे छौड़ी क्षेत्र में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अचानक बोल्डर और मलबा गिरने से मार्ग बाधित हो गया। जानकारी के मुताबिक मलबा गिरने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रियों की आवाजाही रोक दी है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। फिलहाल मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू करने के लिए राहत एवं सफाई कार्य जारी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार देर रात हुई लगातार बारिश के कारण पहाड़ी से बड़े पत्थर और मलबा खिसककर सड़क पर आ गए। इससे सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई और यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं। मलबा और बोल्डर हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गौरीकुण्ड और मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है।

अधिकारियों स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और मौसम की परिस्थितियों पर भी नजर रखी जा रही है। जैसे ही मार्ग सुरक्षित घोषित होगा, यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा। बारिश के चलते केदारघाटी में भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करें।

...हर जरूरी कदम उठा रहा है

रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने कहा है कि मौसम सामान्य होने और मार्ग पूरी तरह साफ होने के बाद ही श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। राहत और बचाव दल लगातार मौके पर जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द मार्ग बहाल कर यात्रा को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है।

यमुना में 5 किलोमीटर तक हजारों मृत मछलियां

वेब वार्ता, कानपुर। कानपुर देहात में यमुना नदी के करीब पाँच किलोमीटर लंबे हिस्से में हजारों मृत मछलियां मिलने से हड़कंप मच गया। नयापुरवा से मनकी पक्के घाट और क्योटरा तक नदी किनारे बिछी मछलियों को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। यह घटना पानी की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले इतनी बड़ी संख्या में मछलियों को मरते नहीं देखा। कुछ मछलियां पानी में तड़पती भी दिखाई दीं। हालांकि, कुछ ग्रामीण मृत मछलियों को अपने घरों में भी ले गए, जिस पर विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य जोखिम की चेतावनी दी है। प्रदूषित या रसायनयुक्त पानी से मरी मछलियों का सेवन गंभीर विषाक्तता का कारण बन सकता है।

प्रारंभिक जांच में आशंका है कि ऊपरी क्षेत्रों से आए प्रदूषित या रसायनयुक्त पानी और नदी में बीओडी (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड) के स्तर में वृद्धि इसकी मुख्य वजह है।

रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पायेगा मौत का कारण

क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी मनोज चौरसिया ने इसकी पुष्टि की कि बारिश के दौरान नदी में सिल्ट और अपशिष्ट पदार्थ बहकर आते हैं, जो जलीय जीवों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के आसपास कोई औद्योगिक इकाई नहीं है, इसलिए प्रदूषित पानी ऊपरी क्षेत्रों से ही आया होगा। नदी के किनारों पर कम जलस्तर और पानी के ठहराव से हानिकारक तत्वों का प्रभाव बढ़ गया हो सकता है। पानी के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मछलियों की मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा।

भारतीय सीमा के करीब अमेरिका-बांग्लादेश ने शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास

ढाका। बांग्लादेश और अमेरिका ने पूर्वोत्तर बांग्लादेश के सिलहट सैन्य क्षेत्र में 13 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग-2026 की शुरूआत विगत दिवस हुई है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा के निकट आयोजित इस अभ्यास को क्षेत्रीय सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह अभ्यास 31 जुलाई तक चलेगा।

डेंगू का कहर, 53 मौतें

वेब वार्ता, कोलंबो। श्रीलंका में मच्छरों से फैलने वाली बीमारी डेंगू का करीब एक दशक में सबसे गंभीर प्रकोप सामने आया है। जनवरी से अब तक 76,044 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 53 मौतें हुई हैं। बीमारी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों के साथ अब देश की सेना भी अभियान में जुट गई है। श्रीलंका की एयरफोर्स ड्रोन की मदद से मानसून की बारिश के बाद छतों पर जमा पानी की पहचान कर रही है। वहीं सेना और पुलिस के जवान घरों, निर्माण स्थलों और स्कूलों की जांच कर रहे हैं, ताकि मच्छरों के पनपने की जगहों को खत्म किया जा सके। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, जुलाई के पहले दो हफ्तों में 18 हजार से ज्यादा मामले सामने आने के बाद अस्पतालों ने बेड बढ़ाने शुरू कर दिए। जून में डेंगू के 21,537 मामले दर्ज किए गए थे।

विपक्ष की एकता में पीएम मोदी ने कर दी सेंधमारी.....शरद पवार और सुप्रिया मिले

वेब वार्ता, नई दिल्ली

जहाँ एक ओर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे विपक्षी दलों के साथ सीजेपी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर मोदी सरकार को घेरने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर संसद परिसर में हुई मुलाकात ने पूरे घटनाक्रम का केंद्र बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार की बैठक की तस्वीरें सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इन तस्वीरों में दोनों नेताओं को मुस्कुराते हुए बातचीत करते देख सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन की बेचैनी बढ़ गई है। यह मुलाकात उस संवेदनशील समय पर हुई है जब पिछले कई दिनों से शरद पवार गुट के एनडीए में शामिल होने या अपने भतीजे अजित पवार के गुट के साथ फिर से एकजुट होने की अटकलें तेज हैं। प्रधानमंत्री आवास से आई इन तस्वीरों ने इन चर्चाओं को और बल दिया है।

तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं शरद पवार का स्वागत करते और दोनों नेताओं को सौहार्दपूर्ण मुद्रा में बातचीत करते देखा जा सकता है, जो राजनीति में अक्सर शब्दों से अधिक संदेश देती हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से कयासों का बाजार गर्म है। सूत्रों के अनुसार, एनसीपी (एसपी) के भीतर भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर मंथन जारी है। चर्चा है कि शरद और अजित पवार के गुट पहले एक हो सकते हैं, इसके बाद एनडीए में शामिल होने की संभावना पर विचार होगा। यदि विलय नहीं भी होता है, तब शरद पवार गुट के अलग से एनडीए में शामिल होने या बाहर से समर्थन देने जैसे विकल्पों पर भी गंभीर बातचीत चल रही है। दावा है कि अगले 8 से 15 दिनों में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। पार्टी के भीतर कई विधायक और सांसद मानते हैं कि सत्ता से दूर रहने की बजाय सरकार का हिस्सा बनने से पार्टी और संगठन को लाभ होगा, जिससे कार्यकताओं का मनोबल बढ़ेगा और पार्टी के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। यह कदम महाराष्ट्र के बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि केंद्र सरकार मानसून सत्र में परिसीमन विधेयक ला सकती है, जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। शरद गुट के पास लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 1 सांसद हैं, जिनका समर्थन ऐसी स्थिति में निर्णायक हो सकता है। हालांकि, एनसीपी (एससीपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया है कि पार्टी के रुख को लेकर चल रही कई खबरें अटकलों पर आधारित हैं।

अब राजनीतिक चर्चाओंका केन्द्र विरोध प्रदर्शन नहीं

महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया था और शरद उसकी सबसे मजबूत कड़ियों में से एक थे। इसके बाद उनके रुख में किसी भी बदलाव का सीधा असर विपक्षी एकता पर पड़ सकता है। फिलहाल न शरद पवार ने कोई औपचारिक घोषणा की है और न ही भाजपा या एनडीए की ओर से कोई पुष्टि हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी हाई-प्रोफाइल मुलाकात और उसके बाद आई तस्वीरों ने इतना अवश्य कर दिया है कि अब राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की बदलती सियासत और उसके इंडिया गठबंधन पर संभावित प्रभाव बन गया है।

मुलाकात की तस्वीर आते ही इंडिया गठबंधन की धड़कनें बढ़ी

समय नहीं है

उन्होंने कहा कि संवैधानिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर फैसला पार्टी के भीतर चर्चा और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से परामर्श के बाद होगा। दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार ने खुद इन अटकलों को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। जब उनसे पार्टी में टूट या एनडीए में जाने की संभावना पर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अभी इस विषय पर बात करने का समय नहीं है। राजनीति में उनकी यह चुप्पी भी कई अर्थों में देखी जा रही है।

संपादकीय

सडकों पर संग्राम

हमने डॉक्टरों के कारखाने खुलते और कारोबार करते देखे हैं। हमने नेताओं के मेडिकल कॉलेज भी देखे हैं। नकली डॉक्टर भी देखे हैं। फर्जी लोगों ने परीक्षाएं भी दी हैं। पेपर लीक भी होते रहे हैं, आत्महत्याएं मन-स्थिति से जुड़ी हैं। किसी सामाजिक, राजनीतिक, पेशेवर समस्या का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हमने इन संवेदनशील मुद्दों पर युवा, छात्र आंदोलन भड़कते नहीं देखे। इस साल भी 11 लाख से अधिक युवाओं ने नीट परीक्षा पास की है, लेकिन उनमें से 9 लाख से अधिक युवाओं को मेडिकल से जुड़े किसी भी कोर्स में दाखिला नहीं मिलेगा। कारण, भारत में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 1.36 लाख से कुछ अधिक ही सीटें हैं। उसके बाद बीडीएस, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी आदि में भी करीब 80,000 सीटें हैं। क्या व्यवस्था है कि युवा ने नीट भी पास कर ली और वह किसी भी तरह डॉक्टर नहीं बन पाया! शेष 9 लाख से अधिक सफल युवा क्या एकदम असफल साबित हो जाएंगे? तो हमारे युवाओं! हिंसक आंदोलन क्यों करते हो? ये तो बंजर है! आत्महत्याएं इस व्यवस्था का समाधान नहीं हैं। देश की आजादी के कुछ साल बाद ही पेपर लीक की घटनाएं सामने आने लगी थीं, शिक्षा-प्रणाली में आज भी विसंगतियां हैं, शिक्षा मंत्री सवालिया होते रहे हैं, लेकिन अनशन कितने हुए? दरअसल राजधानी दिल्ली में आंदोलनजीवी, प्रदर्शनकारियों और उत्पातियों की एक पेशेवर जमात है। उसके चेहरे शाहीन बाग, अन्ना हजारे-केजरीवाल, महिला पहलवानों के प्रदर्शन और किसान आदि आंदोलनों में भी दिखाई दिए। वामपंथी तर्ज पर नारे लगाना और डफली बजाना इनकी खास पहचान है। सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान भी यह जमात सक्रिय रही। उन्हें कौन फंडिंग करता है? मोदी मर जा, शाह मर जा, मोदी को पीटेंगे, अनुच्छेद 370 और आजादी, आजादी सरीखे नारों का शिक्षा की विसंगतियों और नीट पेपर लीक से क्या सरोकार है? यह उपद्रवियों की पेशेवर जमात का खास हुनर है, उनकी पेशेवर टेनिंग है। बीते सोमवार, 20 जुलाई, को संसद सत्र के पहले ही दिन, संसद भवन के 1.5 किमी. के दायरे में, हजारों युवाओं की ऐसी भीड़ आक्रोशित हो गई कि संसद भवन के सभी मोटे-बड़े मेन गेट बंद करने पड़े।

हजारों पुलिसकर्मियों के अलावा, अर्द्धसैनिक बलों, रैपिड एक्शन फोर्स, पानी की तेज बौछार मारने वाले बल के जवानों को सडकों पर उतारना पड़ा। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला एकदम सामने आ गया। बेशक भारत सबसे युवा राष्ट्र है। उसकी करीब 65 फीसदी आबादी की औसतन उम्र 35 साल है। 15-29 साल के आयु-वर्ग के 56 करोड़ से अधिक युवा हैं। वे भारत की ताकत और भविष्य हैं, लिहाजा किसी भी सूरत में उनका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। लेकिन जो भीड़ संसद भवन में घुसना चाहती थी, वह वामदलों, कांग्रेस, आप के छात्र-संगठनों के पेशेवर चेहरे थे। अचानक मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सांसद सरीखे आप नेता और सांसद डिंपल यादव के नेतृत्व में सपा का हुजूम सडकों पर कैसे आ गया? यकीनन यह राजनीतिक कवायद थी। अनशन और संसद चलो का यह कथित आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक है, क्योंकि उनकी पहली मांग शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा है। वांगचुक की भी इच्छा है कि विभिन्न सांसद और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अस्पताल में आकर उनसे मिलें और उनकी मांगों पर आश्वासन दें। बहरहाल यदि यह शैक्षिक प्रदर्शन था, तो किन युवाओं ने पथराव किए, नतीजतन 5 आईपीएस अधिकारियों समेत 118 पुलिसकर्मी घायल हुए। यह कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। बेशक 60 से अधिक प्रदर्शनजीवी भी घायल हुए हैं। करीब 70 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इस पूरे उपद्रव के दौरान एक ऐसा नाम सामने आता रहा, जो कीट-भाव पैदा करता है। कीट-मकौड़ों की जनता नहीं हुआ करती, उनका लोकतंत्र नहीं होता, तिलचट्टे घर-घर पैदा होते रहे हैं, लिहाजा कॉकरोच जनता पार्टी हमारे लोकतंत्र और राजनीतिक दलों पर एक भद्दा मजाक है। उसे राजनीतिक व्यंग्य भी नहीं मान सकते। उसका चुनाव आयोग में कोई पंजीकरण नहीं है और न ही इस नाम से मान्यता दी जानी चाहिए। जनता इनसानों की होती है, जो लोकतंत्र की वाहिका होती है। एक आंदोलन किसी मजाक के आधार पर जवाबदेह नहीं हो सकता, लिहाजा सरकार को सोचना चाहिए कि क्या देश में तिलचट्टों की जनता पार्टी को भी स्वीकृति दी जाए?

प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता का संकट

किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र केवल प्रश्नों का संग्रह नहीं होता, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों, अभिभावकों के त्याग और राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का दस्तावेज होता है। जब किसी प्रतिष्ठित परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की खबर सामने आती है, तो केवल परीक्षा की निष्पक्षता ही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर जनता का विश्वास भी डगमगा जाता है। नीट-यूजी 2026 के पेपर लीक और उसके बाद हुई पुनर्परीक्षा ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता केवल परिणाम घोषित करने में नहीं, बल्कि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में निहित है। यह घटना केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय परीक्षा तंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है, जिसे नजरअंदाज करना भविष्य के लिए महंगा साबित हो सकता है। नीट देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। हर वर्ष लाखों विद्यार्थी डॉक्टर बनने का सपना लेकर वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं। अनेक परिवार अपनी जमा पूंजी बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देते हैं, कुछ ऋण लेते हैं, तो कुछ अपनी आवश्यकताओं में कटौती करते हैं ताकि उनके बच्चे बेहतर तैयारी कर सकें।

ऐसे में यदि परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग जाए, तो सबसे अधिक पीड़ा उन विद्यार्थियों और अभिभावकों को होती है जिन्होंने सफलता का आधार केवल ईमानदार मेहनत को माना होता है। पुनर्परीक्षा आयोजित करना परिस्थितियों में आवश्यक कदम हो सकता है, लेकिन यह कभी भी आदर्श समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि इससे लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों को दोबारा मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। कई विद्यार्थी जो पहले प्रयास में ही आत्मविश्वास से भरे हुए थे, पुनर्परीक्षा के तनाव में अपना संतुलन खो बैठते हैं, और यह अनुभव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ सकता है। इन आंकड़ों और नीतिगत चचाओं के पीछे लाखों वास्तविक चेहरे और कहानियां छिपी होती हैं- वह विद्यार्थी जो रात-रात भर जागकर पढ़ता रहा, वह माता-पिता जिन्होंने अपने सपनों को बच्चे की सफलता में देखा, और वह क्षण जब खबर आती है कि जिस परीक्षा के लिए इतना त्याग किया गया, वही अविश्वसनीय निकली। ऐसे में विद्यार्थियों के मन में उठने वाला गुस्सा और निराशा स्वाभाविक है, और इसे केवल एक तकनीकी या प्रशासनिक चूक के रूप में नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों पर पड़ने वाले वास्तविक भावनात्मक

प्रभाव के रूप में भी समझा जाना चाहिए। यह समस्या केवल नीट तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, कर्मचारी चयन, विश्वविद्यालय प्रवेश और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पेपर लीक अथवा परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। प्रत्येक ऐसी घटना युवाओं के मन में यह प्रश्न छोड़ जाती है कि क्या उनकी वर्षों की मेहनत वास्तव में सुरक्षित है। यदि प्रतिभा के स्थान पर छल और भ्रष्टाचार को अवसर मिलने लगे, तो नुकसान केवल किसी परीक्षा का नहीं होता, बल्कि समाज की नैतिक चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी होता है। प्रतिभाशाली युवाओं का व्यवस्था से विश्वास उठना किसी भी राष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जब मेधावी छात्र यह महसूस करने लगते हैं कि ईमानदारी से अधिक महत्व साधनों और संपर्कों का है, तो वे या तो व्यवस्था छोड़ने का विकल्प चुनते हैं या स्वयं भी अनुचित मार्गों की ओर आकर्षित होने लगते हैं।

यह प्रवृत्ति दीर्घकाल में पूरे समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जवाबदेही है। केवल पेपर लीक करने वाले गिरोहों को गिरफ्तार कर देना पर्याप्त नहीं है। यह भी तय होना चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था कहां विफल हुई, किस स्तर पर लापरवाही हुई, किन अधिकारियों और संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती थी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन-से स्थायी सुधार किए जाएंगे। यदि संस्थागत जवाबदेही तय नहीं होगी, तो हर बार नए नियम बनेंगे, लेकिन समस्याएं बनी रहेंगी। जवाबदेही का अर्थ केवल दंड नहीं, बल्कि व्यवस्था की कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारना भी है। दुर्भाग्यवश, भारत में प्रायः देखा गया है कि किसी बड़ी घटना के बाद कुछ समय के लिए हलचल रहती है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, और फिर धीरे-धीरे मामला ठंडा पड़ जाता है। यही प्रवृत्ति है जिसे तोड़ने की आवश्यकता है। नीट-2026 प्रकरण में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका भी उल्लेखनीय रही। अदालत के हस्तक्षेप ने ही पुनर्परीक्षा जैसे कठिन किंतु आवश्यक निर्णय को संभव बनाया और प्रशासनिक तंत्र पर जवाबदेही का दबाव बनाए रखा। यह दशार्ता है कि जब कार्यपालिका किसी कारणवश निर्णायक कदम उठाने में विलंब करती है, तो न्यायपालिका ही अंतिम भरोसे का स्थान बन जाती है। साथ ही, ऐसे मामलों की तह में जाने पर प्रायः यह भी सामने आता है कि पेपर लीक के पीछे संगठित गिरोहों के साथ-साथ कुछ निजी कोचिंग संस्थानों और बिचौलियों का जाल भी सक्रिय रहता है, जो मोटी रकम लेकर प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का दावा करते हैं। यह गठजोड़ शिक्षा को व्यापार में बदल देता है और ईमानदार विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा को और अधिक असमान बना देता है। जब तक इस तरह के आर्थिक और संस्थागत हितों पर कड़ी नजर नहीं रखी जाएगी, केवल कानून बनाकर समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता।

आज आवश्यकता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए। प्रश्नपत्रों का सुरक्षित डिजिटल एन्क्रिप्शन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, परीक्षा केंद्रों का स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट, संवेदनशील प्रक्रियाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और पेपर लीक के मामलों में त्वरित न्यायिक प्रक्रिया जैसे उपाय समय की मांग हैं। इसके साथ ही परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और नियमित स्वतंत्र समीक्षा भी आवश्यक है। कुछ विशेषज्ञ यह भी सुझाव देते हैं कि परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर, प्रश्नपत्रों के कई सेट तैयार करके और अंतिम क्षण में केंद्र आवंटन कर लीक की संभावनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। विश्वास केवल आश्वासनों से नहीं लौटता, वह निरंतर दिखाई देने वाले सुधारों और निष्पक्ष कार्रवाई से स्थापित होता है। इस संदर्भ में समाज और अभिभावकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

सिकंदर बंसल
शिक्षाविद

पेपर लीक के नाम पर राजनीति का प्रदर्शन नहीं चलेगा

दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद तक निकाले गए तथाकथित "चलो संसद" मार्च ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश में हर आंदोलन वास्तव में जनहित के लिए होता है या फिर कुछ आंदोलन केवल राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए खड़े किए जाते हैं। सोनम वांगचुक के अनशन और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन को जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर समर्थन दिया, उससे यह आंदोलन एक स्वतंत्र जनआंदोलन कम और विपक्षी दलों के राजनीतिक मंचन का प्रयास अधिक दिखाई दिया।

जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकालने की कोशिश के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, कई लोग संसद मार्ग की ओर बढ़े और कुछ प्रदर्शनकारी मेट्रो स्टेशनों तक पहुंच गए, जहां नारेबाजी भी हुई। ऐसे समय में जब संसद का सत्र चल रहा हो और राजधानी में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो, तब बिना अनुमति संसद की ओर मार्च निकालना स्वाभाविक रूप से कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाता है। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान देता है, लेकिन उसके साथ कानून का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि मंच पर और प्रदर्शन में कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया, आतिशी, संजय सिंह और अन्य विपक्षी नेताओं की मौजूदगी ने यह संदेश दिया कि आंदोलन अब शिक्षा सुधार की मांग से आगे बढ़कर राजनीतिक रंग ले चुका है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि यह वास्तव में छात्रों का आंदोलन था तो फिर विपक्षी दलों की इतनी सक्रिय भूमिका क्यों दिखाई दी।

पेपर लीक का मुद्दा निश्चित रूप से गंभीर है और किसी भी परीक्षा में अनियमितता होने पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को विफल घोषित कर देना या हर परीक्षा को संदेह के घेरे में खड़ा कर देना उचित नहीं कहा जा सकता। लाखों विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम के बाद परीक्षाएं दीं और बड़ी संख्या में छात्रों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर अपनी मेहनत का प्रमाण दिया। ऐसे में यह कहना कि पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उन लाखों ईमानदार विद्यार्थियों की मेहनत का भी अपमान माना जा सकता है।

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि देश की शिक्षा व्यवस्था का बड़ा हिस्सा दशकों तक उन्हीं सरकारों के अधीन विकसित हुआ, जिनका नेतृत्व कांग्रेस ने किया। यदि आज विपक्ष शिक्षा सुधार की बात करता है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए उसने कौन-सी ऐसी व्यवस्था विकसित की थी जिसने भविष्य की चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित किया। केवल वर्तमान सरकार पर आरोप लगाना और अतीत की जिम्मेदारियों से दूरी बना लेना राजनीतिक सुविधा तो हो सकती है, लेकिन यह संतुलित दृष्टिकोण नहीं माना जा सकता।

यह भी देखने योग्य है कि इस पूरे आंदोलन में अभिजीत दीपके को प्रमुख चेहरा बनाया गया, लेकिन वास्तविक राजनीतिक समर्थन विपक्षी दलों की ओर से दिखाई दिया। इससे यह धारणा बनती है कि दीपके एक ऐसे चेहरे के रूप में सामने लाए गए हैं, जिसके माध्यम से विपक्ष अपनी राजनीतिक रणनीति को आगे बढ़ाना चाहता है। आंदोलन के पीछे वास्तविक शक्ति कौन है, इसका उत्तर प्रदर्शन में शामिल राजनीतिक दलों की सक्रियता स्वयं देती हुई प्रतीत होती है।

देश इस समय आधारभूत संरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, परिवहन और वैश्विक कूटनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, आर्थिक विस्तार और विकास परियोजनाओं को दुनिया गंभीरता से देख रही है। ऐसे समय में यदि हर उपलब्धि के बीच लगातार असंतोष का माहौल तैयार करने का प्रयास हो, तो यह भी स्वाभाविक है कि उसके पीछे की राजनीति पर चर्चा होगी। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना आवश्यक है, लेकिन आलोचना तथ्यों और संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन का स्थान महत्वपूर्ण होता है, परंतु आंदोलन तभी प्रभावी होते हैं जब वे निष्पक्षता, तथ्यों और जनहित पर आधारित हों। यदि किसी आंदोलन का स्वरूप धीरे-धीरे राजनीतिक दलों के शक्ति प्रदर्शन में बदल जाए, तो उसके मूल उद्देश्य पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। संसद मार्च के दौरान जिस प्रकार विपक्षी दलों की सक्रिय भागीदारी सामने आई, उससे यह धारणा मजबूत हुई कि यह केवल शिक्षा सुधार का अभियान नहीं बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास भी था। लोकतंत्र में जनता अंतिम निर्णायक होती है। वह यह समझती है कि कौन-सा आंदोलन वास्तविक जनहित के लिए है और कौन-सा आंदोलन राजनीतिक लाभ के लिए। शिक्षा सुधार पर गंभीर चर्चा अवश्य होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए रचनात्मक संवाद, संस्थागत सुधार और ठोस नीति आवश्यक है, न कि केवल सड़क पर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन। देश के विद्यार्थियों का भविष्य किसी भी दल की राजनीति से ऊपर होना चाहिए और शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय को केवल राजनीतिक संघर्ष का माध्यम बनाने से बचना चाहिए।

कांतिलाल मांडोत

संसद का मानसून सत्र,सड़कों का संघर्ष और लोकतांत्रिक असहमति की अग्निपरीक्षा

भारत का लोकतंत्र केवल संसद भवन की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। उसकी वास्तविक शक्ति संसद के भीतर होने वाली बहस और संसद के बाहर जनता की आवाज-दोनों के संतुलन में निहित है। संसद कानून बनाती है, जबकि जनता समय-समय पर आंदोलनों के माध्यम से सत्ता को आईना दिखाती है। किंतु जब संसद की ओर बढ़ते कदमों को बैरिकेड,लाठी,आँसू गैस और अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे का सामना करना पड़े,तब प्रश्न केवल कानून- व्यवस्था का नहीं रह जाता; वह लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा प्रश्न बन जाता है।

संसद के वर्तमान मानसून सत्र ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या भारत में लोकतांत्रिक असहमति का दायरा सिमट रहा है,अथवा सुरक्षा चुनौतियों के कारण प्रशासन पहले से अधिक सतर्क और कठोर हो गया है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद केवल जनप्रतिनिधियों का भवन नहीं, बल्कि देश की 140 करोड़ जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का सर्वोच्च प्रतीक है। भारतीय लोकतंत्र का इतिहास बताता है कि बड़े राजनीतिक परिवर्तन केवल संसद के भीतर नहीं हुए। सन 1974 का लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन सत्ता परिवर्तन का कारण बना। 1975 का आपातकाल लोकतांत्रिक अधिकारों पर सबसे बड़ा प्रहार माना गया। 2011 में अन्ना हजारे के जनलोकपाल आंदोलन ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध देशव्यापी जनमत तैयार किया और राजनीति की दिशा बदल दी। 2020झ21के किसान आंदोलन ने अंततः केंद्र सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेने पर विवश किया। इन घटनाओं ने सिद्ध किया कि लोकतंत्र में संसद और सड़क कभी विरोधी नहीं, .बल्कि एक-दूसरे को दिशा देने वाली संस्थाएँ रही हैं। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वर्तमान मानसून सत्र के दौरान राजधानी दिल्ली का दृश्य अनेक प्रश्न छोड़ जाता है। संसद मार्ग और उसके आसपास का इलाका अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में बदल गया। बहुस्तरीय बैरिकेडिंग,बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती,संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश नियंत्रण तथा प्रदर्शनकारियों को संसद तक पहुँचने से रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए। प्रशासन ने इसे संसद की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया, जबकि विपक्षी दलों और प्रदर्शनकारियों ने इसे लोकतांत्रिक विरोध पर कठोर अंकुश बताया। लोकतंत्र में सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। संसद की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। इसके बाद संसद परिसर को देश के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में विकसित किया गया। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त सतर्कता असामान्य नहीं कही जा सकती। किंतु दूसरी ओर यह भी उतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को शांतिपूर्ण और अहिंसक ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार भी देता है। लोकतंत्र की कसौटी यही है कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

वर्तमान घटनाक्रम में सबसे अधिक चिंता का विषय संवाद का अभाव दिखाई देता है। जब सरकार और आंदोलनकारी दोनों स्वयं को सही साबित करने में लग जाएँ और संवाद की जगह टकराव ले ले,तब लोकतंत्र का नैतिक बल कमजोर पड़ने लगता है। संसद के भीतर यदि बहस बाधित हो और बाहर विरोध को केवल कानून- व्यवस्था का विषय मान लिया जाए,तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ आवश्यकता से अधिक कठोरता बरती गई,जबकि प्रशासन का कहना है कि संसद की सुरक्षा सर्वोपरि थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों के अपने- अपने तर्क हैं। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सकता था?क्या संवाद,समन्वय और बेहतर भीड़-प्रबंधन से टकराव टाला जा सकता था?राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआर बी)के आँकड़े बताते हैं कि देश में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ा है। दूसरी ओर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक सूचकांकों में भारत में नागरिक स्वतंत्रताओं और विरोध प्रदर्शनों को लेकर समय- समय पर बहस होती रही है। यही कारण है कि संसद मार्ग पर होने वाली प्रत्येक घटना केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहती,बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा बन जाती है। इतिहास बताता है कि किसी भी लोकतंत्र की शक्ति उसके विरोध को सुनने की क्षमता में होती है। ब्रिटेन,अमेरिका,फ्रांस और अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी संसदों के बाहर बड़े प्रदर्शन होते रहे हैं। कई बार पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है,किंतु अंततः समाधान संवाद और राजनीतिक सहमति से ही निकलता है। भारत भी इसी लोकतांत्रिक परंपरा का उत्तराधिकारी है।

आज आवश्यकता किसी राजनीतिक विजय की नहीं,बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास की पुनर्स्थापना की है। सरकार को यह विश्वास दिलाना होगा कि असहमति को राष्ट्र-विरोध नहीं माना जाएगा। विपक्ष को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि लोकतांत्रिक विरोध हिंसा, अव्यवस्था या सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान में परिवर्तित न हो। पुलिस की भूमिका भी पूरी तरह निष्पक्ष,संयमित और कानून सम्मत होनी चाहिए,क्योंकि लोकतंत्र में पुलिस किसी सरकार की नहीं,बल्कि संविधान की प्रहरी होती है। घायल कितने हुए,कितनों को हिरासत में लिया गया और किसने पहले बैरिकेड तोड़ा – इतिहास अंततः इन प्रश्नों को पीछे छोड़ देता है। इतिहास केवल इतना याद रखता है कि उस समय लोकतंत्र ने संवाद चुना था या टकराव। संसद का सम्मान तभी सुरक्षित रहेगा जब जनता को भी यह विश्वास होगा कि उसकी आवाज संसद तक पहुँच सकती है। संसद का वर्तमान मानसून सत्र समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी बदल जाएँगे,लेकिन यह प्रश्न बना रहेगा कि क्या भारत का लोकतंत्र असहमति को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता और अधिक मजबूत करेगा,या बैरिकेडों के दोनों ओर खड़े लोग एक-दूसरे को केवल प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते रहेंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय किसी एक दल की जीत में नहीं,बल्कि उस व्यवस्था में होती है जहाँ संसद की गरिमा भी सुरक्षित रहे और नागरिक कीआवाज भी सम्मान पूर्वक सुनी जाए। यही भारतीय गणराज्य की आत्मा है, यही संविधान की भावना है और यही लोकतंत्र का स्थायी मार्ग भी।

लेखक- विनोद कुमार सिंह तकियावाला
(स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तम्भकार)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

आलेख

चकाचौंध का अर्थशास्त्र व खो रही संवेदनाएं

अभी दो दिन पहले ही भारतीय क्रिकेट दल की इंग्लैंड यात्रा समाप्त हुई है। यहां लेख के आरंभिक वाक्य में ही क्रिकेट शब्द लिखने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि यह पूरा लेख क्रिकेट पर आधारित होगा। इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड के मध्य बीस ओवरों के पांच तथा पचास ओवरों के तीन खेल आयोजित किए गए थे। इन कुल आठ मैचों में से एक भी मैच ऐसा नहीं था, जो अपराह्न या रात्रि काल में खेला गया हो। सभी मैच प्रातःकाल और मध्याह्न काल में सूर्य प्रकाश में ही खेले गए। किसी भी मैच में कृत्रिम प्रकाश अर्थात विद्युतीय प्रकाश का उपयोग नहीं किया गया। अमरीका-ईरान युद्ध के आरंभ होने से पहले भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तीव्रतापूर्वक अग्रसर था, किंतु गत तीन-चार माह में भारत दो-तीन श्रेणी नीचे गिरकर सातवीं अर्थव्यवस्था हो गया और जापान व इंग्लैंड क्रमशः पांचवीं व चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब भारतीय क्रिकेट दल ब्रिटेन में एकदिवसीय एवं बीस ओवरों के मैच खेल रहा था, तब ब्रिटेन दुनिया का ऐसा देश था जो भारत से अधिक अर्थसमृद्ध था।

भारत से अधिक धनसंपन्न होने के बाद भी ब्रिटेन के शासन ने रात्रिकालीन क्रिकेट मैच नहीं करवाए। ब्रिटेन की तुलना में यदि भारत को देखें तो यहां टेस्ट क्रिकेट के मैचों को छोडकर अन्य लघु क्रिकेटीय प्रारूप के मैच दिवसीय (प्राकृतिक) प्रकाश में होते ही नहीं हैं। यह अत्यंत विचारणीय है कि जब भारत से अधिक अर्थसमृद्ध देश तथा स्वयं क्रिकेट खेल का जनक ब्रिटेन भी क्रिकेट के मैचों में विद्युत का अपव्यय न करके सूर्यप्रकाश में ही सारे मैच संपन्न करा रहा है, तो ऐसा भारत में क्यों नहीं हो रहा है? भारत का वर्तमान शासन जिस राजनीतिक दल के नेतृत्व में चल रहा है, वह दल निस्संदेह अभी तक शासकीय तंत्र का उचित संचालन कर रहा है, किंतु यह भी एक कटु सत्य है कि शासन की विकासदृष्टि आधुनिकता, वैज्ञानिकता तथा प्रगति की समृद्धता के अभिशापों को निरंतर अनदेखा कर रही है। अपने देश को दुनिया में सबसे आगे खड़ा करने की महत्त्वाकांक्षा बुरी नहीं है। हमारा देश विश्व का सबसे समृद्ध, सुंदर और हर दृष्टि से जीवनानुकूल देश हो, ऐसी अभिलाषा, चाहे राजनीतिक हो अथवा आर्थिक, बुरी नहीं है, बल्कि अच्छी ही है, किंतु क्या इसके लिए हमें मानवों के जीवन का दिन-रात, चौबीसों घंटे अमानवीयता की पराकाष्ठा तक दोहन करना चाहिए? क्रिकेट को कृत्रिम प्रकाश में आधी रात तक खेलने-खिलाने का जो खेल भारत में चला आ रहा है, क्या वह वास्तव में क्रिकेट खेल की भलाई के लिए है? लगता तो नहीं है कि इस योजना से क्रिकेट खेल का भला होगा। वास्तविकता यह है कि सरकारी हो अथवा निजी, दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य रूप से आठ-नौ घंटों तथा ओवरटाइम के बाद असामान्य रूप से बारह-चौदह घंटों तक काम करने वाले लोगों को, काम के बाद घर आने पर या घर आने तक लगने वाले समय में भी उनके द्वारा खरीदे गए दूरभाषिक इंटरनेट डेटा के माध्यम से उनके धन को सजीव क्रिकेट प्रसारण में निवेश करवाने की गरज से ही अति मात्रा में रात्रिकालीन क्रिकेट खेला व खिलाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) को धनार्जन की इतनी हवस लगी हुई है कि उसने नवंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक महिलाओं की, बीस ओवरों की, दो विश्व कप श्रृंखलाएं आयोजित कर डालीं। भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। देश की अधिक जनसंख्या कई वर्षों से फिल्मों एवं क्रिकेट में विशेष रुचि रखती आई है। कुछ वर्षों से, विशेषकर कोरोना काल के बाद इस जनसंख्या की रुचि सोशल मीडिया में भी बहुत अधिक विकसित हुई है। शासन को क्या चाहिए था? फिल्मों एवं क्रिकेट को सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित करने के बाद तो इन दो क्षेत्रों से शासन की आय कई गुना बढ़ गई है। तब से शासन के माध्यम से जनता की इसी रुचि को भुनाया जा रहा है। शासन ने एक मनुष्य को मशीन से भी अधिक निर्जीव मान लिया है। शासन चाहता है कि मानव रूपी मशीन को वह अपनी शासकीय प्रतिष्ठा, समृद्धि एवं प्रगति के लिए जितना अधिक घिसेगा, वह उतना ही अधिक प्रतिष्ठित, समृद्ध व प्रगतिगामी होगा।

मानव को मशीन से भी अधिक बड़ी मशीन समझकर अपने हिसाब से हांकने का खेल केवल क्रिकेट एवं फिल्मों के क्षेत्र में ही नहीं हो रहा है, अन्य क्षेत्रों में भी मानव और मानवीयता की ऐसी ही दुर्दशा है। ऐसे में शासन से प्रश्न है कि इन परिस्थितियों में स्वयं मनुष्य, उसके परिवार, उनसे मिलकर बनने वाले समाज, ग्राम, कस्बों, नगरों, महानगरों, राज्यों तथा सर्वोपरि देश या कहें राष्ट्र का प्राकृतिक औचित्य क्या रह जाता है! सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से अति बनकर प्रसारित हो रहे क्रिकेट, फिल्मों तथा अन्य क्षेत्रों के प्रसारण को एक सीमित क्षमताधारी मानव अंततः कितना व कब तक सहन कर सकता है? अब मानव की सहनशीलता क्षीण हो चुकी है। वह इतना आत्मकेंद्रित हो चुका है कि अपने अलावा किसी का भी अच्छा-बुरा अस्तित्व स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। इस स्थिति में पूरी दुनिया विचित्र मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा अपरिचित रोगों से ग्रस्त है। आधुनिक विकास की अंधी दौड़, कृत्रिम जीवनशैली और मानवीय चेतना का निरंतर हो रहा दोहन एक गंभीर तथा विचारणीय स्थिति है। ब्रिटेन जैसे विकसित देश के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बाद भी वह प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करता है तथा सूर्य के प्रकाश में क्रिकेट मैचों का आयोजन कर विद्युत ऊर्जा जैसे अमूल्य संसाधन का अपव्यय रोकता है। इसके विपरीत, भारत में व्यावसायिक हितों, विज्ञापनों और कॉर्पोरेट लाभ के लिए आधी रात तक कृत्रिम प्रकाश में मैच आयोजित कराए जाते हैं। यह विरोधाभास हमारी नीतिगत प्राथमिकताओं तथा दूरदर्शिता की कमी को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। समस्या केवल ऊर्जा के अपव्यय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव आम जनमानस के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

दिन-रात बारह से चौदह घंटे हाड़तोड़ परिश्रम करने वाले आम नागरिक को मनोरंजन के नाम पर डिजिटल मीडिया तथा देर रात तक चलने वाले खेल प्रसारणों का अभ्यस्त बनाया जा रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य उपभोक्तावाद को बढ़ावा देकर आम जनता की जेब से पैसा निकालना और शासन तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की कमाई बढ़ाना है। क्रिकेट, सिनेमा एवं सोशल मीडिया का यह घातक त्रिकोण मानव को एक संवेदनहीन एवं विचारशून्य मशीन में परिवर्तित कर रहा है। प्रगति तथा राष्ट्र निर्माण की आकांक्षा निःसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु यदि इस प्रगति की नींव में मानव मूल्यों का विनाश एवं प्राकृतिक संतुलन का ह्रास छिपा हो, तो ऐसी समृद्धि अंततः खोखली ही सिद्ध होती है। अत्यधिक काम, अनिद्रा तथा डिजिटल लत के कारण आज का समाज विचित्र मानसिक तनाव, एकांतवास और अस्वाभाविक जीवनशैली का शिकार हो रहा है। व्यक्ति धीरे-धीरे अत्यधिक आत्मकेंद्रित एवं संवेदनहीन बनता जा रहा है, जिससे सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न होने की कगार पर है। शासन तथा समाज दोनों को ही इस स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझना होगा। विकास का अर्थ केवल आर्थिक आंकड़े या चकाचौंध बढ़ाना नहीं, बल्कि मानव जीवन की सहजता, स्वास्थ्य और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना है। यदि समय रहते इस अमानवीय कुव्यवस्था तथा अंधाधुंध व्यावसायीकरण पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, तो जिस समृद्ध राष्ट्र का स्वप्न हम देख रहे हैं, उसमें जीवन जीने योग्य स्वस्थ एवं संवेदनशील मानव ही शेष नहीं बचेंगे।

विकेश कुमार बडोला
स्वतंत्र स्तंभकार

संक्षिप्त वार्ता

पूर्व लक्ष्मी नगर विधायक नितिन त्यागी को 2019 के मामले में बरी किया

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेब वार्ता)। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व लक्ष्मी नगर विधायक नितिन त्यागी को वर्ष 2019 के एक मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में उन पर यमुना फ्लडप्लेन की बहाली और पुनरुद्धार कार्य कर रहे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के ठेका मजदूरों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। साथ ही अदालत ने बचाव पक्ष के वकील की उस कार्रवाई की निंदा की जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण गवाह को अदालत के बाहर बुलाया था। मजिस्ट्रेट ने कहा कि बचाव पक्ष की यह हरकत इस अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। मामला लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज 2019 के एक प्राथमिकी पर आधारित है। आरोप था कि 29 नवंबर 2019 को तत्कालीन विधायक नितिन त्यागी अपने सहयोगियों के साथ यमुना फ्लडप्लेन पर चल रहे पुनरुद्धार कार्य स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने मजदूरों के साथ मारपीट की, सरकारी साइट प्लान फाड़ दिए और अधिकारियों को धमकाते हुए फ्लडप्लेन से अतिक्रमण हटाने का काम रोकने की कोशिश की। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद नितिन त्यागी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम हैंडल बैन

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेब वार्ता)। कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम हैंडल बैन कर दिया गया है। अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए अभिजीत दीपके ने लिखा कि नरेंद्र मोदी ने कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करवा दिया है। हालांकि कुछ देर बाद ही इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से शुरू हो गया। फिलहाल सुचारू रूप से काम कर रहा है।

डीटीयू का ओरिएंटेशन कार्यक्रम 27 जुलाई को

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेब वार्ता)। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) ने बीटेक और बी डिजाइन कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए 27 जुलाई को ओरिएंटेशन कम इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसको लेकर डीटीयू ने सूचना जारी कर दी है। इस कार्यक्रम में अभिभावक भी शामिल हो सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान छात्रों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रणाली, अनुसंधान एवं नवाचार गतिविधियों, विभिन्न छात्र क्लबों, सुविधाओं, अनुशासन, परीक्षा प्रणाली और कैंपस जीवन के बारे में बताया जाएगा।

इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सेवानिवृत्त आईपीएस और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉ. किरण बेदी शामिल होंगी। जबकि डीटीयू के पूर्व छात्र एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व प्रमुख कर्नल सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (ब्लैक कैट्स) की काउंटर टेरर टास्क फोर्स के पूर्व फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर गौतम गांगुली (सेवानिवृत्त) विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता डीटीयू के कुलपति प्रो. प्रतीक शर्मा करेंगे।

ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति योजना की समय-सीमा बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जसविंदर सिंह जौली ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्रिमंडल मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 2 महीने बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री और मंत्री को भेजे पत्र में जसविंदर सिंह जौली ने कहा कि योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून को समाप्त हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी समय पर आवेदन नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि समय-सीमा बढ़ने से अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

डीटीयू ने पीएचडी दाखिला को लेकर अस्थायी सूची की जारी

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) ने अगस्त 2026 सत्र के लिए पीएचडी दाखिला के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों की प्रोविजनल (अस्थायी) सूची जारी कर दी है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि चयन पूरी तरह मूल दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता की पुष्टि के बाद होगा। चयनित उम्मीदवारों को 24 जुलाई को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाणपत्र साथ लाने होंगे। ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र पीएचडी दाखिला के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

16 मेट्रो स्टेशन बंद होने से यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

मंडी हाउस पर केवल लाइन परिवर्तन की सुविधा

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेब वार्ता)। सुरक्षा कारणों से राजधानी दिल्ली में बुधवार को मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रहीं। कई प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद किए जाने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से कार्यालय, अस्पताल और हवाई अड्डे की ओर जाने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में लंबा समय लगा।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर 16 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इस दौरान वायलेट लाइन पर केवल मंडी हाउस स्टेशन पर लाइन परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध रही, जबकि यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकलने अथवा प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अचानक लागू हुई व्यवस्था के कारण कई स्टेशनों पर भ्रम की स्थिति बनी रही। सेंट्रल सेक्रेट्रिएट और मंडी हाउस जैसे व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार घोषणाओं के माध्यम से बदली हुई व्यवस्था की जानकारी दी जाती रही। मंडी हाउस स्टेशन पर निगम के कर्मचारी और परिचालन दल यात्रियों को बताते रहे कि वहां केवल लाइन परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध है।

सेंट्रल सेक्रेट्रिएट स्टेशन पर लाइन परिवर्तन की सुविधा बंद रहने से पीली लाइन के यात्रियों को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई यात्री स्टेशन परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों से वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लेते दिखाई दिए। मेट्रो सेवाओं में व्यवधान के चलते बड़ी संख्या में यात्रियों ने बस, टैक्सी और ऑटो जैसे वैकल्पिक साधनों का सहारा लिया। इससे प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ गया। यात्रियों का आरोप है कि कुछ स्थानों पर वाहन चालकों ने अधिक किराया भी वसूला।

स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए बंद किए गए सभी 16 मेट्रो स्टेशनों और प्रमुख लाइन परिवर्तन केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। विशेष रूप से राजीव चौक सहित संवेदनशील स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों से अनुमति मिलने के बाद ही प्रभावित स्टेशनों पर सामान्य आवागमन बहाल किया जाएगा। निगम ने यात्रियों से यात्रा से पहले नवीनतम परिचालन संबंधी जानकारी प्राप्त करने और आवश्यकतानुसार वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है।

दिल्ली में 84 सरकारी सेवाएं अब कम समय में, कुछ काम तुरंत होंगे

लाइसेंस, परमिट और मंजूरियां तेजी से मिलेंगी, कारोबार करना होगा आसान

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली में सरकारी सेवाएं अब पहले से कम समय में मिलेंगी। दिल्ली सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम के तहत मिलने वाली 84 सेवाओं के निपटारे की समय सीमा घटा दी है। कुछ सेवाएं अब आवेदन के तुरंत बाद उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से नागरिकों और कारोबारियों दोनों को तेज, पारदर्शी और आसान सेवाएं मिलेंगी।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने डिरेगुलेशन एक्सरसाइज फेज-2 के तहत 18 विभागों की 95 प्रमुख सेवाओं की समीक्षा की है। इस दौरान आवेदन से लेकर अंतिम मंजूरी तक पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया गया। जहां अनावश्यक औपचारिकताएं मिलीं, वहां प्रक्रिया को सरल बनाया गया और समय सीमा कम करने का फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि कुछ सेवाओं में प्रक्रिया इतनी आसान कर दी गई है कि आवेदन के बाद उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जा सकेगा। हालांकि किन सेवाओं में यह सुविधा मिलेगी, इसकी अलग से सूची जारी की जाएगी।

कारोबार के लिए राहत

सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए विभिन्न लाइसेंस, परमिट, मंजूरी और क्लीयरेंस के लिए एक ही मंच पर आवेदन किया जाता है। समय सीमा घटने से उद्योग और व्यापार जगत को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मंजूरियों में देरी कम होने से नए निवेश और कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया तेज होगी।

डिजिटल गवर्नेंस पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डिजिटल तकनीक और प्रक्रिया सुधार के जरिए लोगों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है।

बारिश से राजधानी की हवा रही साफ

वायु गुणवत्ता सूचकांक 64 अंक पर रहा

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेब वार्ता)। राजधानी में पिछले तीन दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश और तेज हवाओं के चलते प्रदूषण का स्तर काफी कम रहा। इस कारण लगातार दूसरे दिन बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 से नीचे रहा। इस वर्ष यह 17वां दिन है, जब वायु गुणवत्ता का स्तर 100 से नीचे दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता के लिहाज से देखें तो दिल्ली वालों के लिए यह सबसे अच्छा दौर चल रहा है।

राजधानी में खासतौर पर मानसून के मौसम में ही वायु गुणवत्ता सबसे अच्छी रहती है। पिछले तीन दिनों में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हल्की से तेज बारिश हुई है। इस दौरान हवा की गति भी आमतौर पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही। इसके चलते हवा में घुले प्रदूषक कण काफी हद तक साफ हो गए हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 64 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले मंगलवार को यह सूचकांक 69 अंक पर रहा था।

यहां की हवा रही सबसे साफ

दिल्ली के शूटिंग रेंज में वायु गुणवत्ता सबसे ज्यादा साफ रही। यहां का सूचकांक 33 अंक पर रहा। ध्यान चंद स्टेडियम का सूचकांक 34 और इग्नू का सूचकांक 37 अंक पर रहा। सीपीसीबी के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष नौ जुलाई को वायु गुणवत्ता सबसे ज्यादा साफ रही थी। इस दिन वायु गुणवत्ता का स्तर 48 अंक पर रहा था।

पटियाला हाउस कोर्ट के पास आधुनिक सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेब वार्ता)। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट के पीछे नवनिर्मित आधुनिक सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर परिषद के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुराने शौचालय को हटाकर लगभग 50 वर्गमीटर क्षेत्र में 22 लाख रुपये की लागत से नया शौचालय बनाया गया है। यह निर्माण कार्य लगभग 5 माह में पूरा किया गया।

उन्होंने बताया कि नए शौचालय में महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पुरुष खंड में 3 जल शौचालय और 5 संवेदक आधारित मूत्रालय, जबकि महिला खंड में 3 जल शौचालय बनाए गए हैं। इससे जल संरक्षण के साथ स्वच्छता को भी बढ़ावा मिलेगा।

चहल ने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र में वर्तमान में 364 सार्वजनिक स्वच्छता इकाइयां संचालित हैं, जिनमें 291 सार्वजनिक शौचालय, 40 सामुदायिक शौचालय और 33 सार्वजनिक मूत्रालय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह नई सुविधा पटियाला हाउस कोर्ट आने वाले अधिवक्ताओं, वादकारियों, न्यायालय कर्मियों और आम नागरिकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक सुविधाओं का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने और उन्हें स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की।

सुसाइड नोट लिखने के बाद घर से निकला किशोर, मेट्रो स्टेशन पर पकड़ा

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेब वार्ता)। सुसाइड नोट लिखने के बाद घर से निकले 17 वर्षीय किशोर को सीआईएसएफ जवानों की मदद से दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पता लगाकर उसके परिवार से मिला दिया गया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे पश्चिमी दिल्ली स्थित पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन की है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने सीआईएसएफ के नियंत्रण कक्ष को जानकारी दी थी कि 17 साल का किशोर एक नोट लिखने के बाद घर से निकल गया है।

जंतर-मंतर प्रदर्शन पर निशिकांत दुबे के आरोप, सरकार से जांच की मांग

नई दिल्ली, वेब वार्ता

जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन को बाहरी तत्वों का समर्थन प्राप्त है तथा पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जानी चाहिए। हालांकि, उनके इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि 20 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास के निकट हुए विपक्ष के प्रदर्शन के कारण उनके पुत्र को परीक्षा केंद्र पहुंचने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के चलते परीक्षार्थियों और आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन का उल्लेख करते हुए सांसद ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाएं हुईं और पुलिस अधिकारियों पर हमला किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदर्शन को कुछ बाहरी तत्वों और बांग्लादेशी नागरिकों का समर्थन प्राप्त है। साथ ही उन्होंने इन सभी आरोपों की विस्तृत जांच कराने की मांग की। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके विदेश दौरों और विभिन्न व्यक्तियों से हुई मुलाकातों की भी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

उधर, प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम को लेकर विभिन्न पक्षों के अलग-अलग दावे सामने आए हैं। प्रदर्शनकारी संगठनों का आरोप है कि संसद मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। इस बीच, दिल्ली में जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया है और हाल के घटनाक्रम से संबंधित मामलों की जांच जारी होने की बात कही है।

प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और उससे जुड़े आरोप-प्रत्यारोप को लेकर विभिन्न मामलों की सुनवाई न्यायालय में भी जारी है। ऐसे में घटनाओं के संबंध में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

जीएसटी अपील में देरी तो नहीं मिलेगा मौका, सरकार ने समय सीमा की तस्वीर साफ की

एक अप्रैल के बाद मिले आदेशों पर तीन महीने के भीतर दाखिल करनी थी अपील

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली के कारोबारियों के पास जीएसटी आदेशों के खिलाफ अपील करने का अब आखिरी मौका बचा है। उपराज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एक अप्रैल 2026 या उसके बाद मिले जीएसटी आदेशों के खिलाफ अपील आदेश मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर दाखिल करनी थी। अप्रैल और मई में आदेश पाने वालों के लिए अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है या अंतिम दौर में है।

अब तक जीएसटी अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की समय सीमा को लेकर असमंजस था। नई अधिसूचना ने स्पष्ट किया है कि एक अप्रैल 2026 को आधार तिथि माना जाएगा और इसके बाद मिले सभी आदेशों पर तीन महीने की वैधानिक अवधि लागू होगी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन कारोबारियों पर पड़ेगा, जिन्हें अप्रैल-मई में आदेश मिले थे।

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि एक अप्रैल से पहले संप्रेषित आदेशों के खिलाफ अपील की अंतिम तिथि 30 जून थी। यह अधिसूचना जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 112 के तहत जीएसटी परिषद की सिफारिश पर जारी की गई है और इसे दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।

प्रजापति महासभा के सामूहिक विवाह समारोह में 11 कन्याओं का विवाह संपन्न

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेब वार्ता)। प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश के तत्वावधान में छतरपुर मंदिर स्थित मार्कण्डेय भवन में आयोजित 27वें प्रजापति सामूहिक विवाह समारोह में 11 कन्याओं का विवाह वैदिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। समारोह के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर लाभ उठाया। कार्यक्रम का शुभारंभ अशोक प्रजापति तथा प्रजापति महासभा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। विवाह समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की।

एम्स दिल्ली में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के पदों के नाम बदले, भर्ती नियम रहेंगे पुराने

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेब वार्ता)। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने इमरजेंसी मेडिसिन से जुड़े फैकल्टी पदों के नामों में बदलाव किया है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी (इमरजेंसी मेडिसिन) और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑथोपेंडिक्स (इमरजेंसी मेडिसिन), दोनों पद असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के नाम से जाने जाएंगे। एम्स की फैकल्टी सेल के प्रशासनिक अधिकारी राज कुमार भारद्वाज के अनुसार, इन पदों के नाम बदलने के लिए संस्थान की एकेडमिक कमेटी और गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दे दी है। हालांकि, इन पदों पर नियुक्ति के लिए पहले से तय भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एम्स के प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार, यह फैसला 15 जुलाई 2024 को हुई एकेडमिक कमेटी की बैठक और 12 सितंबर, 2025 को हुई गवर्निंग बॉडी की 163वीं बैठक में मंजूर प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। एम्स प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पदों के नाम में बदलाव केवल प्रशासनिक और विभागीय पहचान को बेहतर बनाने के लिए किया गया है।

जनपथ में कल से हस्तशिल्प का बड़ा उत्सव

नई दिल्ली, वेब वार्ता

जनपथ स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में 24 जुलाई से सात अगस्त तक वीव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल आयोजित होगा। इसमें देशभर की पारंपरिक हथकरघा बुनाइयों और हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी। वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) और सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम (सीसीआईसी) के संयुक्त प्रयास से यह आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी रोजाना सुबह 11 से रात 8 बजे तक खुली रहेगी। इसमें देश की 116 पारंपरिक हथकरघा बुनाइयों के साथ विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बुनकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।

आंदोलन और मेट्रो बंदी का 15 साल पुराना रिश्ता, इस बार सबसे लंबा इंतजार

अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ सिलसिला, निर्भया, किसान आंदोलन, जी-20 और अब 17 स्टेशनों की तक पहुंचा

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली में जब भी कोई बड़ा आंदोलन या हाई सिक्योरिटी आयोजन होता है, सबसे पहले असर मेट्रो पर दिखता है।

पहले पुलिस सड़कें बंद करती थी, अब मेट्रो के गेट भी बंद करा दिए जाते हैं। बुधवार को सुबह करीब 9 बजे से 17 स्टेशन बंद किए गए, जिससे सवाल उठा कि क्या कानून-व्यवस्था का सबसे बड़ा हथियार अब मेट्रो बंद करना बन गया है। बुधवार की कार्रवाई इसलिए अलग है क्योंकि देर शाम तक डीएमआरसी यह नहीं बता सका कि स्टेशन कब खुलेंगे। अगले आदेश तक बंद की घोषणा से हजारों यात्रियों को वैकल्पिक रास्ते तलाशने पड़े। ऑफिस जाने वालों से लेकर मरीजों, छात्रों व पर्यटकों तक सभी को परेशानी उठानी पड़ी।

मेट्रो बंद करने की शुरूआत 2011 के अन्ना आंदोलन में हुई, जहां उद्योग भवन, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, खान मार्केट व रेसकोर्स स्टेशन बंद किए गए। 2012 में निर्भया आंदोलन, 2020-21 के किसान आंदोलन, 26 जनवरी 2021 की ट्रैक्टर परेड और सितंबर 2023 के जी-20 सम्मेलन में भी चुनिंदा स्टेशनों पर पाबंदी लगी, लेकिन कुछ घंटों या निर्धारित कार्यक्रम के बाद स्टेशन खोल दिए गए।

देर शाम तक नहीं खोला गया और...

बुधवार की कार्रवाई इस मायने में अलग है कि सुबह से बंद 17 स्टेशनों को देर शाम तक नहीं खोला गया और खुलने का समय भी घोषित नहीं किया, जिससे यह हाल के वर्षों की सबसे लंबी अनिश्चितकालीन सुरक्षा बंदियों में शामिल हो गई है।

संक्षिप्त वार्ता

देवरिया राजकीय बाल गृह से नौ वर्षीय बालक फरार, पुलिस खोजबीन में जुटी

वेब वार्ता, देवरिया

देवरिया जिले के राजकीय बाल गृह बालक में रहने वाला नौ वर्षीय बालक पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज से फरार हो गया। एक होमगार्ड उसे प्रतिदिन पढ़ने के लिए साथ लेकर स्कूल जाता था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान वह कक्षा से चकमा देकर बुधवार को भागने में सफल रहा। कोतवाली पुलिस बालक की तलाश कर रही है।

पुलिस के अनुसार देवरिया जिले के राजकीय बाल गृह बालक में रहने वाला बालक स्कूल में कक्षा नौ में पढ़ता था। प्रतिदिन पूरी सुरक्षा के बीच एक होमगार्ड उसे पढ़ने के लिए स्कूल ले जाता था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसे साथ लेकर राजकीय बाल गृह जाता था। स्कूल की छुट्टी के समय जब होमगार्ड कक्षा में पहुंचा तो बालक गायब था उसने इस बात को प्रधानाचार्य को बताई तो खलबली मच गई। बाल गृह बालक के अधीक्षक समेत कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल के सीसी कैमरे खंगाले गए। जिसमें दोपहर तक बालक स्कूल की कक्षा व आस पास दिखा है। उसके बाद वह कैमरे में नहीं दिख रहा है। इससे पता चलता है कि वह दोपहर बाद कक्षा से किसी बहाने लापता हुआ है। दो माह पूर्व भी एक बालक चहारदीवारी फांद कर फरार हो गया था। उसे पकड़ने में कोतवाली पुलिस को एक माह बाद सफलता मिली।

इस संबंध में कोतवाली देवरिया के प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राकेश राय ने बताया कि बालक के पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज से लापता होने की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। सीसी कैमरे की फुटेज देखने के साथ ही बालक को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध भण्डारण पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई

वेब वार्ता, कुशीनगर

कुशीनगर जिले में कृषकों को निर्धारित मूल्य पर उच्च गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध परिवहन एवं अनधिकृत भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार सिंह के निर्देशन में की गई कार्रवाई में दो अलग-अलग मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई गई है ।जिसमें विगत 20 जुलाई 2026 को की गई कार्रवाई के दौरान मथौली बाजार से रामकोला की ओर अवैध रूप से ले जाई जा रही 20 बोरी यूरिया उर्वरक पकड़ी गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त उर्वरक साधन सहकारी समिति, मथौली बाजार से अवैध रूप से भेजा जा रहा था। इसके उपरांत समिति का निरीक्षण किए जाने पर पी.ओ.एस. मशीन में दर्ज स्टॉक के सापेक्ष 428 बोरी यूरिया तथा 192 बोरी डी.ए.पी. उर्वरक मौके पर उपलब्ध नहीं पाए गए। प्रथम दृष्टया यह उर्वरक वितरण में गंभीर अनियमितता एवं हेराफेरी का मामला पाए जाने पर साधन सहकारी समिति, मथौली बाजार के सचिव रामसागर सिंह के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

इसी क्रम में प्राप्त एक अन्य शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 21 जुलाई 2026 को कृष्ण कुमार पुत्र स्वामीनाथ कुशवाहा, निवासी ग्राम मठिया विशम्भर, माधोपुर, पोस्ट सेखवनिया के परिसर में छापेमारी की गई। निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की 47 बोरी उर्वरक का भण्डारण पाया गया। जांच में संबंधित व्यक्ति के पास उर्वरकों के भण्डारण एवं विक्रय के लिए कोई वैध प्राधिकार-पत्र उपलब्ध नहीं मिला। यह कृत्य उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध पाए जाने पर संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

इस संबंध में देवरिया के जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने आज बताया कि जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं एवं सहकारी समितियों को निर्देशित किया गया है कि उर्वरकों का वितरण पूर्णतः शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़, कालाबाजारी, अवैध भण्डारण अथवा उर्वरकों की हेराफेरी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

श्रावण मास कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी ने राजघाट का किया निरीक्षण

वेब वार्ता, हरदोई। आगामी श्रावण मास कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से बुधवार को पुलिस अधीक्षक हरदोई ने थाना बिलग्राम क्षेत्र के राजघाट का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रियों के आवागमन मार्ग, राजघाट

परिसर, बैरिकेडिंग, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए और श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम वातावरण उपलब्ध कराया जाए। पुलिस अधीक्षक ने संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, निरंतर गश्त, प्रभावी यातायात प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित अधिकारी पूरी तरह सतर्क एवं तैयार रहें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूर्ण कर लिया जाए, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कचहरी परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कांग्रेस ने जंतर-मंतर की घटना की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने, कथित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने, घायल छात्रों को निःशुल्क उपचार व मुआवजा उपलब्ध कराने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक आधार पर इस्तीफा लेने या उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में भी संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की मांग उठाई गई।

सम्मान किया जाना चाहिए

जिला कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम पांडे ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने वाले छात्रों पर बल प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुपम दीक्षित ने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से होना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।

आवश्यक कार्रवाई की मांग की

प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष शिवा पाल, अजीत सिंह चंदेल, एडवोकेट भुट्टो मियां, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहन सिंह, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अजीत विशाल नंदवंशी, सेवा दल जिला अध्यक्ष शिवम अग्निहोत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. राजीव सिंह, शहर उपाध्यक्ष उमा राजवंशी, पी.पी. वर्मा, गोपाल पांडे, मोहम्मद आजम, शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अंकित पाल, अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विनीत वर्मा, पीसीसी सदस्य आशीष पाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की।

आत्मा की बैठक में डीएम अनुनय झा के निर्देश

किसानों तक समयबद्ध पहुंचे योजनाओं का लाभ

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में बुधवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में कृषि तकनीकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) की शासी निकाय एवं प्रबंध समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि एवं संबद्ध विभागों द्वारा संचालित योजनाओं तथा आत्मा योजना के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण तथा कृषि यंत्रीकरण के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि आत्मा योजना के तहत किसान प्रशिक्षण, भ्रमण कार्यक्रम, किसान गोष्ठियों और तकनीकी प्रदर्शन का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसान नई तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकें।

बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि यंत्रीकरण, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन सहित विभिन्न कृषि आधारित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पात्र किसानों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने किसानों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कृषि विभाग से खरीफ एवं रबी सीजन की तैयारियों, गुणवत्तायुक्त बीज और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता तथा किसानों को समय पर तकनीकी सलाह उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को कहा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा व्याडवाल, उप कृषि निदेशक राजेश यादव, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चंद्रा सहित कृषि एवं संबद्ध विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ऐलानः शहीद मेजर पंकज पांडेय के नाम पर होगा हरदोई मेडिकल कॉलेज

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। कारगिल के वीर सपूत अमर शहीद मेजर पंकज कुमार पांडेय की पुण्यतिथि पर आयोजित प्रतिमा अनावरण समारोह में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हरदोई मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद मेजर पंकज कुमार पांडेय के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ब्रजेश पाठक ने शहीद मेजर पंकज कुमार पांडेय की प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने परिसर में पौधरोपण किया और शहीद की स्मृतियों से जुड़े प्रदर्शनों का अवलोकन

भी किया। इस दौरान उन्होंने शहीद के पिता अवधेश कुमार पांडेय को सम्मानित किया।

अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर पंकज कुमार पांडेय ने विषम परिस्थितियों में मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अपने साथी सैनिक को बचाने के लिए उन्होंने अपने

प्राण न्योछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि हरदोई की माटी के इस वीर सपूत पर पूरा प्रदेश गर्व करता है और आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदान से प्रेरणा मिलती रहेगी।

...और बलिदान को नमन किया

ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरदोई के विकास के लिए भी सरकार निरंतर कार्य करती रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी ने की। उन्होंने मेजर पंकज कुमार पांडेय के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अन्य वक्ताओं ने भी शहीद के अदम्य साहस और बलिदान को नमन किया।

किसानों को नवाचार और मूल्य संवर्धन अपनाने की सलाह

वेब वार्ता,हरदोई। विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता तथा मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में किसान दिवस का आयोजन हुआ। बैठक में किसानों की समस्याएं सुनने के साथ कृषि, सिंचाई, विद्युत और सहकारिता से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए बिजली कनेक्शन के लिए यदि विद्युत लाइन से उपभोक्ता के घर की दूरी 300 मीटर तक है तो केबल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए निर्धारित कनेक्शन शुल्क 5,000 से 8,000 रुपये जमा करना होगा।

गैस सिलेंडर लेने जा रही महिला को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने रौंदा, मौत

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। कोतवाली क्षेत्र के पाली रोड पर आगमपुर गांव के पास बुधवार सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए चालक की तलाश शुरू कर दी है।

पाली थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी रामकली (55) पत्नी रामकरण बुधवार सुबह अपने पुत्र धीरज के साथ बाइक (यूपी 30 सीएच 4417) से सिरोमननगर गैस एजेंसी घरेलू गैस सिलेंडर लेने जा रही थीं। सुबह करीब 11 बजे आगमपुर गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में रामकली सड़क पर गिर गईं और ट्रॉली के पहिए के नीचे आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।

हरदोई में खुरपका-मुंहपका टीकाकरण अभियान के आठवें चरण का शुभारंभ

8.38 लाख पशुओं को लगेगा निःशुल्क टीका

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जिलाधिकारी अनुनय झा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) टीकाकरण अभियान के आठवें चरण का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान टीकाकरण के लिए गठित टीमों को रोस्टर के अनुसार गांवों में रवाना किया गया, जो पशुपालकों के घर-घर पहुंचकर निःशुल्क टीकाकरण करेंगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने जनपद के सभी पशुपालकों से अपील की कि टीकाकरण के दौरान टीमों को पूरा सहयोग दें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक टीकाकृत पशु का विवरण उसके कान के छल्ला (ईयर टैग) नंबर के साथ भारत पशुधन ऐप पर अपलोड किया जाएगा।

अभियान का शुभारंभ विकास खंड मल्लावां में विधायक आशीष सिंह 'आशू' तथा विकास खंड माधौगंज में विधायक की माता श्रीमती विमला देवी द्वारा भी हरी झंडी दिखाकर किया गया। इसके अलावा जिले के अन्य विकास खंडों में प्रमुखों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी अभियान की शुरूआत कराई। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के अनुसार यह अभियान 22 जुलाई से 8 सितंबर 2026 तक कुल 45 दिनों तक संचालित होगा। इस दौरान जनपद के 8.38 लाख गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं का खुरपका-मुंहपका रोग से बचाव के लिए निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आठ माह से अधिक गर्भवती पशुओं तथा चार माह से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी एवं पशुमित्र सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

दो रोडवेज बसों के बीच फंसकर महिला की मौत

बांगरमऊ जाने के लिए कर रही थीं बस का इंतजार

वेबवार्ता, हरदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित रोडवेज बस अड्डे पर बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 32 वर्षीय महिला की जान चली गई। निजी दवा कंपनी में कार्यरत नेहा सिंह दो रोडवेज बसों के बीच फंस गईं। गंभीर रूप से घायल नेहा को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

देहात कोतवाली क्षेत्र के खेतुई गांव निवासी नेहा सिंह बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे रोडवेज बस अड्डे पर उन्नाव के बांगरमऊ में आयोजित कंपनी की आधिकारिक बैठक में शामिल होने के लिए बस का इंतजार कर रही थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इसी दौरान हरदोई और कन्नौज डिपो की दो रोडवेज बसें एक साथ आगे बढ़ीं। अचानक हुए इस घटनाक्रम में नेहा दोनों बसों के अगले हिस्से के बीच फंस गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं।

हादसे के बाद बस अड्डे पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।

मृतका के परिजनों ने दोनों बस चालकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चालकों ने यह सुनिश्चित किए बिना बसें आगे बढ़ा दीं कि सामने कोई व्यक्ति मौजूद है या नहीं। यदि सावधानी बरती जाती तो हादसा टाला जा सकता था।

मृतका के देवर वीरेश सिंह ने बताया कि करीब दस वर्ष पहले नेहा के पति सर्वेश सिंह, जो ट्रक चालक थे, एक सड़क दुर्घटना में डीसीएम और ट्रक के बीच फंसने से जान गंवा चुके थे। पति की मौत के बाद नेहा ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और नौकरी कर अपने 15 वर्षीय बेटी रिया सिंह तथा 11 वर्षीय बेटे विवेक का पालन-पोषण कर रही थीं। इस हादसे के बाद परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

गौसगंज में ई-रिक्शा शोरूम की दीवार काटकर लाखों की चोरी, पुलिस जांच में जुटी

वेबवार्ता/हरदोई। थाना कासिमपुर के अंतर्गत ग्राम गौसगंज में बांके बाबा एजेंसी ई-रिक्शा शोरूम की मंगलवार रात दीवार काटकर नकदी सहित बैट्री, मोटर सहित लाखों रुपए की चोरी की घटना को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया। पीड़ित व्यवसायी ने पूरे मामले की सूचना थाना कासिमपुर में दी है। बताते चले थाना कासिमपुर के अंतर्गत ग्राम सभा गौसगंज में अच्छी मार्केट है, कस्बा के रूप में मार्केट विकसित है। कई वाहनों की एजेंसी, शोरूम, कई दर्जन सराफा की दुकानें, कपड़े, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, किराना सहित मार्केट में सैकड़ो दुकानें हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण चोरी की घटनाएं अक्सर होती हैं। इसी क्रम में मंगलवार की रात गौसगंज में स्थित बांके बाबा एजेंसी ई-रिक्शा शोरूम में मंगलवार की रात दीवार काटकर शोरूम में रखी 13 ई रिक्शा बैटरी, 5 हजार रुपये की नकदी, पांच मोटर सहित अन्य सामान कीमत दो लाख रुपये की चोरी की घटना को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया। पीड़ित व्यवसायी मानवेंद्र सिंह पूरे मामले की सूचना थाना कासिमपुर को दी है। घटना की सूचना पर कासिमपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हरदोई की बिटिया चेतना शुक्ला को राजधानी लखनऊ में मिला प्रतिष्ठित सम्मान

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई/लखनऊ। जनपद हरदोई की प्रतिभाशाली फिल्म अभिनेत्री चेतना शुक्ला को राजधानी लखनऊ में आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था जन समस्या मेला समिति भारत के 11वें स्थापना दिवस एवं नागरिक सम्मान समारोह के दौरान कला क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।

गोमती नगर स्थित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह वत्स एवं उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु के पूर्व उपनिदेशक दिनेश कुमार सहगल ने किया। समारोह की अध्यक्षता संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फिल्म अभिनेता सतेंद्र सिंह यादव 'हीरो भैया' ने की, जबकि सह-अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट (डॉ.) अंकित मित्तल ने की।

समारोह में कला, समाजसेवा, न्याय और पत्रकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में हरदोई की बेटी चेतना शुक्ला को स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि वीरेंद्र प्रताप सिंह वत्स ने कहा कि अपनी प्रतिभा के साथ संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना पूरे हरदोई के लिए गर्व की बात है।

सम्मान प्राप्त करने के बाद चेतना शुक्ला ने आयोजन समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें भविष्य में और बेहतर कार्य करने के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा देगा। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

महत्वपूर्ण ख़बर

सिंधु जल समझौते पर भारत का रुख और सख्त: बहाली से इनकार

- नई दिल्ली। सिंधु जल समझौते को लेकर भारत ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह समझौता अब अपने मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं रहेगा। सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा लगातार दिए जा रहे समर्थन के विरोध में भारत ने साफ कर दिया है कि पुरानी शर्तों और व्यवस्था के तहत अब कोई बातचीत या समझौता संभव नहीं है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यद्यपि भारत फिलहाल विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1960 में हुई इस संधि से पूरी तरह बाहर निकलने पर तुरंत विचार नहीं कर रहा है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसे जारी रखना अपने राष्ट्रीय हित में नहीं मानता।

20 किमी के अंदर रहने वालों को नहीं देना होगा टोल, अब डिजिटल पास बनेंगे

- नई दिल्ली। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले है, तो अब बार-बार टोल चुकाने या पास बनवाने के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। नेशनल हाईवे अथॉरिटीऑफइंडिया(एनएचएआई) ने ऐसे लोगों के लिए डिजिटल ह्यलोकल पासह्ल की सर्विसेस शुरू कर दी है। इस पास की मदद से एलिजिबल लोग एक महीने तक संबंधित टोल प्लाजा से अनलिमिटेड बार सफर कर सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि पूरा काम अब मोबाइल से कुछ ही मिनटों में हो जाएगा।

एनएचएआई ने यह सुविधा फिलहाल दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 पर स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा से शुरू की है। आने वाले महीनों में इसे देश के दूसरे टोल प्लाजा पर भी लागू किया जाएगा। यह कदम मल्टी-लेन फ्री फ्लो यानी बिना बैरियर वाले टोल सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

कनाडा ने पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की मदद का किया ऐलान

भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिशों के बीच बड़ा कदम

टोरंटो। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की पाकिस्तान यात्रा के समापन से ठीक पहले कनाडा ने इस्लामाबाद को 47 मिलियन डॉलर (करीब 4.7 करोड़ डॉलर) से अधिक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है।

यह धनराशि पाकिस्तान में विकास कार्यों और सुरक्षा पहलों पर खर्च की जाएगी। कनाडा का यह कदम ऐसे समय में आया है जब वह भारत के साथ अपने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को फिर से पटरी पर लाने का निरंतर प्रयास कर रहा है।

जानकारी के अनुसार, इस पैकेज में से 2.2 मिलियन डॉलर से अधिक की नई फंडिंग सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए दी गई है, जिसमें इंटरपोल, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के संयुक्त प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा, कनाडा से जुड़े तीन विकास आधारित प्रोजेक्ट्स के लिए 45 मिलियन डॉलर की राशि मंजूर की गई है। इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाते हुए भारत के खिलाफ कनाडा से कूटनीतिक समर्थन की मांग भी की।

भारत और कनाडा के रिश्तों में पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान काफी कड़वाहट आ गई थी, जब सरे में हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर अनर्गल आरोप लगाए गए थे। हालांकि, हाल ही में कनाडाई पुलिस प्रशासन (आरसीएमपी) ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच और दर्ज आरोपों में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता की ओर इशारा करता हो, और भारत ने जांच में पूरा सहयोग दिया है। कनाडा में नए नेतृत्व और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के पद संभालने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तेजी से सुधार देखा गया है। अमेरिका पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत कनाडा भारत के साथ साझेदारी मजबूत कर रहा है। इसी साल कनाडाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को लेकर द्विपक्षीय समझौते हुए थे। इसके अलावा, जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री के बीच हुई सकारात्मक बैठकों ने दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी संबंधों की प्रतिबद्धता को और दृढ़ किया है।

सोनम वांगचुक के समर्थन में अमेरिका से यूरोप तक प्रदर्शन

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली। शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में अब आंदोलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जोर पकड़ने लगा है।

अमेरिका के न्यूयॉर्क और सैन होजे सहित यूरोप के लंदन, बर्लिन, नीदरलैंड और आयरलैंड में भी भारतीय मूल के लोगों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा कथित परीक्षा अनियमितताओं पर जवाबदेही की मांग उठाई।

अमेरिकी संगठन 'हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स' के बैनर तले न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने और सैन होजे में प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सोनम वांगचुक के समर्थन में नारे लगाए तथा केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की।

संगठन के अनुसार, इसी प्रकार के एकजुटता प्रदर्शन लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और डबलिन स्थित भारतीय दूतावास के बाहर भी आयोजित किए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भारत के विद्यार्थियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए तथा सरकार को छात्रों की चिंताओं पर खुला संवाद शुरू कर आवश्यक सुधार लागू करने चाहिए।

उल्लेखनीय है कि सोनम वांगचुक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों और कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें जंतर-मंतर से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर उनका उपचार जारी है। इस बीच देश में कई विपक्षी दलों ने भी उनके समर्थन में प्रदर्शन किए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते समर्थन को शिक्षा सुधार की मांग को वैश्विक स्तर पर मिल रही सहानुभूति के रूप में देखा जा रहा है।

अफगानिस्तान में बाढ़: 20 की मौत, 100 से अधिक लापता

काबुल। पूर्वी अफगानिस्तान में अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। प्राकृतिक आपदा के कारण कम से कम 20 लोगों की जान चली गई है, जबकि 80 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। अफगानिस्तान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, इस त्रासदी का सबसे भीषण प्रभाव पूर्वी प्रांत नूरिस्तान और पारून के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिला है, जहां सैकड़ों मकान और उपजाऊ कृषि भूमि पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं।

राहत और बचाव एजेंसियां प्रभावित इलाकों में लापता लोगों की तलाश और पीड़ितों की सहायता के लिए युद्धस्तर पर अभियान चला रही हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में बाढ़ के प्रचंड बहाव में ताश के पत्तों की तरह ढहते कच्चे घर और असहाय लोग साफ देखे जा सकते हैं। इस प्राकृतिक प्रकोप के बीच मौसम विभाग ने देश के 34 में से 10 प्रांतों में भारी बारिश, तेज आंधी और फ्लैश फ्लड की नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदियां और जोखिम वाले संवेदनशील इलाकों के पास रहने वाले निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सख्त हिदायत दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस भीषण आपदा के पीछे केवल मूसलाधार बारिश ही जिम्मेदार नहीं है। दशकों से जारी युद्ध और संघर्ष के कारण जर्जर हो चुका इंफ्रास्ट्रक्चर, कमजोर अर्थव्यवस्था, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और अधिक विकराल बना दिया है। अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में अधिकांश मकान मिट्टी के बने हैं, जो अचानक आने वाले पानी के तेज बहाव और भूस्खलन के सामने टिक नहीं पाते। उल्लेखनीय है कि चालू वर्ष की शुरूआत में भी अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 110 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी।

ताजा बाढ़ ने एक बार फिर देश में आपदा प्रबंधन प्रणाली और कमजोर ढांचे की भयावह स्थिति को उजागर कर दिया है।

काले कपड़े पहन संसद पहुंचे सांसदों ने किया जोरदार प्रदर्शन

पेपर लीक और शिक्षा की बदहाली को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाले गए संसद तक मार्च में छात्रों के साथ की गई बर्बरता के विरोध में बुधवार सुबह प्रमुख विपक्ष के सांसद काले लिवास पहन संसद पहुंचे। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत अखिलेश यादव व अन्य विपक्षी सांसद नारे लगाते नजर आए।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन से ही पेपर लीक और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वाला मुद्दा गूंज रहा है। विपक्ष ने संसद तक मार्च के दौरान युवाओं पर की गई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा है। मंगलवार को पीएम आवास के करीब कांग्रेस के धरने के दौरान राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया और कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद यह प्रदर्शन दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्यों तक पहुंच गया है। जगह-जगह लोग प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां दे रहे हैं। इसे देखते हुए बुधवार सुबह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तौर पर अनेक सांसद काले लिवास में संसद पहुंचे हैं और प्रदर्शन किया है।

संसद के मानसून सत्र में यह मुद्दा लगातार गूंजा है। विपक्ष पेपर लीक के साथ ही देश की बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। इसके अलावा अब प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर रहा है। बताया जा रहा है कि इस कारण दिल्ली के बाहर भी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अनेक प्रमुख शहरों से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए आने की सुचनाएं आ रही हैं।

पीएम आवास प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी बलपूर्वक गिरफ्तार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की ओर कांग्रेस के विरोध मार्च के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी घायल हो गए। बाद में पुलिस राहुल-प्रियंका-अखिलेशसहिततमामप्रदर्शनकारियों को उठाकर ले गयी। कांग्रेस द्वारा जारी तस्वीरों और वीडियो में राहुल गांधी की नाक से खून निकलता दिखाई दिया। पार्टी का आरोप है कि प्रदर्शन रोकने के दौरान दिल्ली पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की धक्का-मुक्की में उन्हें चोट लगी।

कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य विपक्षी नेता छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे। इसी दौरान बैरिकेडिंग पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया और जबरन हटाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इसी अफरा-तफरी में राहुल गांधी को चोट आई और बाद में उन्हें हिरासत में भी लिया गया। राहुल गांधी के घायल होने की तस्वीरें सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की। पार्टी ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध को बलपूर्वक दबाने की कोशिश की गई। वहीं, सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के आरोपों

को खारिज करते हुए कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने टकराव का रास्ता चुना। समाचार लिखे जाने तक दिल्ली पुलिस की ओर से राहुल गांधी की चोट के कारणों पर विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।

इससे पूर्व दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के निकट बड़ा प्रदर्शन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता विरोध मार्च में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की और सरकार उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र अपने भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के बजाय बल प्रयोग कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस पूरे घटनाक्रम पर जवाब देने की मांग की। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अस्पताल जाकर घायल प्रदर्शनकारियों से भी मुलाकात की थी। वहीं, प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को आगे बढ़ने से रोका। कुछ समय तक धरने और नारेबाजी के बाद पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल और गरमा गया। उधर, केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दे को भड़का रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए और कुछ प्रदर्शनकारियों का व्यवहार उग्र था।

बिहार के कनिष्क नारायण बने ब्रिटेन में मंत्री, लिसा नंदी की कुर्सी बरकरार

लंदन। ब्रिटेन में राजनीतिक परिवर्तन के बाद नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने औपचारिक रूप से देश की कमान संभाल ली है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से नए राजनीतिक मॉडल की प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री बर्नहैम ने अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है।

इस नए मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के दो प्रमुख नेताओं को अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो ब्रिटेन की राजनीति में भारतीय समुदाय के बढ़ते प्रभाव को दशार्ता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्मे कनिष्क नारायण को बर्नहैम सरकार में कैबिनेट स्तर का दर्जा देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री नियुक्त किया गया है। मुजफ्फरपुर से 12 वर्ष की आयु में यूके चले गए कनिष्क ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक और अमेरिका की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की शिक्षा प्राप्त की। सिलिकॉन वैली और टेक सेक्टर में वर्षों के अनुभव के बाद, उन्होंने 2024 के चुनावों में लेबर पार्टी के टिकट पर वेल ऑफ ग्लैमरगन सीट से जीत दर्ज की थी। इससे पहले वे सरकार में जूनियर मंत्री के रूप में कार्यरत थे।

दूसरी ओर, भारतीय मूल की वरिष्ठ सांसद लिसा नंदी को बर्नहैम कैबिनेट में संस्कृति सचिव के पद पर बरकरार रखा गया है। मैनचेस्टर में जन्मी लिसा नंदी का भारत के कोलकाता शहर से गहरा पारिवारिक संबंध है।

उम्मीद भी जगाती है

राजनीति में आने से पूर्व सामाजिक क्षेत्रों में नीतियों पर कार्य कर चुकीं लिसा 2010 में पहली बार विगन सीट से सांसद चुनी गई थीं। वे उस क्षेत्र से सांसद बनने वाली पहली महिला और पहली एशियाई नेता बनीं। ब्रिटेन की इस नई कैबिनेट में भारतीय मूल के इन दोनों कद्दावर नेताओं की मौजूदगी न केवल उनके राजनीतिक कद को बढ़ाती है, बल्कि भारत और ब्रिटेन के संबंधों में नए आयाम जोड़ने की उम्मीद भी जगाती है।

पाकिस्तान में गरीबी का धमाका, 10 में से 3 लोग गरीबी रेखा के नीचे

इस्लामाबाद। गंभीर आर्थिक तंगी और लगातार बेतहाशा महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में आम लोगों की जिंदगी बेहाल हो चुकी है। देश में छाई आर्थिक मंदी का असर अब आंकड़ों में भी साफ नजर आने लगा है, जिसके तहत पाकिस्तान में अब हर 10 में से लगभग 3 लोग (28.9प्रतिशत) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। हालिया हाउसहोल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट के आंकड़ों के आधार पर यह डरावनी तस्वीर सामने आई है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 में पाकिस्तान की गरीबी दर 21.8प्रतिशत थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 28.9 प्रतिशत हो चुकी है। यानी महज छह सालों के भीतर देश में गरीबों की संख्या में काफी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगभग छह सालों के लंबे अंतराल के बाद सामने आए ये आंकड़े

बताते हैं कि आर्थिक अस्थिरता ने आम नागरिकों का जीना मुश्किल कर दिया है। इस आर्थिक बदहाली का सबसे भयंकर प्रहार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी पर हुआ है। शहरों की तुलना में गांवों में गरीबी ज्यादा तेजी से बढ़ी है, जिससे शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच की आर्थिक खाई और चौड़ी हो गई है। पिछले छह वर्षों के दौरान गांवों में गरीबी दर में लगभग 8 प्रतिशत अंकों का इजाफा दर्ज किया गया है, जबकि शहरों में यह बढ़ोतरी करीब 6 प्रतिशत अंक रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बार-बार आते आर्थिक संकट, कोविड-19 महामारी का असर, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें और कड़े आर्थिक सुधारों का पूरा बोझ देश के गरीब तबके पर पड़ा है। विश्लेषक आम पाकिस्तानियों के लिए इसे खोया हुआ दशक (लॉस्ट डिकेड) करार दे रहे हैं। महंगाई के अनुपात में परिवारों की आय और खर्च में लगातार गिरावट आई है, जिससे साफ पता चलता है कि विकास के तमाम दावों के बावजूद आम पाकिस्तानी परिवार आज कुछ साल पहले की तुलना में और भी बदतर स्थिति में पहुंच गए हैं।

300 से अधिक स्टॉपेज होंगे खत्म, बचेगा समय और ईंधन

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे लंबी दूरी और प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाने जा रही है। देश भर में विभिन्न ट्रेनों को दिए गए 300 से अधिक प्रायोगिक (प्रायोगिक आधार पर दिए गए) ठहराव को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का खाका तैयार किया गया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से यात्रियों के सफर के समय में 15 से 45 मिनट तक की कमी आएगी। यह योजना अक्टूबर 2026 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

सीएम थलपति ने कहा- नीट परीक्षा पूरी तरह खत्म करें

नई दिल्ली। देशभर में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में धांधली और पेपर लीक के आरोपों को लेकर विरोध का माहौल बना हुआ है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से जारी प्रदर्शनों के बीच तमिलनाडु में तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थलपति विजय की

राजनीतिक पार्टी तमिझगा वेत्री कजगम (टीवीके) ने नीट परीक्षा पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी ने मांग की है कि केवल परीक्षा में धांधली रोकना ही काफी नहीं है, बल्कि नीट प्रवेश परीक्षा को हमेशा के लिए पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। छात्रों के भविष्य और राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की वकालत करते हुए टीवीके ने शिक्षा नीति में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। पार्टी का मानना है कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि इसमें कोई कानूनी बाधा आती है, तो एक अंतरिम उपाय के तहत विशेष समवर्ती सूची बनाई जानी चाहिए, ताकि राज्य सरकारों को अपनी मेडिकल शिक्षा और प्रवेश प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण मिल सके।

मणिपुर में उग्रवाद को बड़ा झटका: केसीपी के 46 उग्रवादियों ने हथियारों सहित किया आत्मसमर्पण

इंफाल। मणिपुर में उग्रवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीपुल्स वॉर ग्रुप) [केसीपी (पीडब्ल्यूजी)] के 46 सक्रिय कैडरों ने मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह की मौजूदगी में इंफाल ईस्ट स्थित मणिपुखरी गैरीसन में आयोजित होम कमिंग सेरेमनी के दौरान आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया।

आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों ने 28 हथियार भी सुरक्षा बलों के हवाले किए, जिनमें एके सीरीज राइफलें, इंसास राइफल, एसएलआर, .303 राइफल, कार्बाइन, पिस्तौल, सिंगल और डबल बैरल बंदूकें, एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) लॉन्चर, मैगजीन, गोला-बारूद और विस्फोटक शामिल हैं।

मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने कहा कि राज्य में शांति बहाल करने के प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार के गठन के बाद अब तक करीब 1,200 हथियार बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें 600 लूटे गए हथियार भी शामिल हैं। उन्होंने अन्य उग्रवादियों से भी हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत मुख्यधारा में लौटने की अपील की।

गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजाम ने इसे मई 2023 के संघर्ष के बाद केसीपी (पीडब्ल्यूजी) का पहला बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण बताया। अधिकारियों के अनुसार असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से यह सफलता मिली है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि 46 उग्रवादियों के एक साथ आत्मसमर्पण से संगठन की गतिविधियों और प्रभाव को बड़ा झटका लगा है तथा राज्य में शांति और स्थिरता स्थापित करने के प्रयासों को नई मजबूती मिलेगी।

ताजा खबर

संक्षिप्त

सभी विभागों की योजनाएं, सेवाएं होंगी ऑनलाइन

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार साधक सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा है कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विभिन्न प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया दो वर्ष से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सूची विभागावार अद्यतन कर ली जाए। मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक में ई-ऑफिस, आधार बेस अटेंडेंस, लोक सेवा गारंटी, सूचना के अधिकार, सुश्वर छत्तीसगढ़, नियद नेल्लानार योजना, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आई-गॉट के तहत विभागवार चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की जाये। अधिकारी-कर्मचारियों को आई-गॉट के तहत विभाग की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाने कहा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए। बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, समेत सभी अधिकारी मौजूद थे।

ओपन कैंपस प्लेसमेंट, 7 कंपनियों से 62 युवाओं को मिला रोजगार

रायपुर। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सड्डू में सोमवार को आयोजित ओपन कैंपस प्लेसमेंट एवं अप्रेंटिसशिप मेले में युवाओं को रोजगार के उत्कृष्ट अवसर प्राप्त हुए। इस मेले में सात प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लेकर विभिन्न ट्रेडों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए रोजगार और अप्रेंटिसशिप के दरवाजे खोले। मेले में कुल 74 प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। कंपनियों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, तकनीकी और व्यक्तिगत साक्षात्कार की प्रक्रिया के बाद 62 प्रशिक्षणार्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया। इस कैंपस में सात प्रतिष्ठित औद्योगिक कंपनियों ने रोजगार के अवसर दिए। 74 प्रशिक्षणार्थी पहुंचे थे जिसमें से अंतिम रूप से 62 का चयन हुआ। संस्था के प्राचार्य नरेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि कौशल विकास, अनुशासन और निरंतर सीखने की ललक ही एक सफल करियर की मजबूत नींव है। उन्होंने चयनित युवाओं को अपने कार्यस्थल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्था और राज्य का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। गरियाबंद. खरीफ मौसम 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 जुलाई तक अपना बीमा करा सकते हैं. कलेक्टर की अध्यक्षता में 16 जुलाई को हुई जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए. बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ 2026 के लिए जिले में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, कोदो, कुटकी और रागी फसलों को अधिसूचित किया गया है. योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक, बटाईदार और वनपट्टाधारी किसान ले सकते हैं. जिले के लिए बीमा कंपनी के रूप में बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस को अनुबंधित किया गया है. कितना देना होगा प्रीमियम कृषि विभाग के अनुसार अनाज, दलहन और तिलहन फसलों के लिए कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत और लघुधान्य फसलों के लिए 1 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को देना होगा. धान सिंचित के लिए 66 हजार

डेयरी योजना में सब्सिडी के लिए सरपंच का निवास प्रमाण पत्र अमान्य

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तहसीलदार का ही मान्य

सरकारी योजनाओं में पात्रता के लिए कड़े नियम

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी शासकीय योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण केवल तहसीलदार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र से ही सिद्ध होगा। न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की एकलपीठ ने रायपुर निवासी जसपाल सिंह द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता ने राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी के लिए आवेदन किया था। उन्होंने बैंक आफ महाराष्ट्र से 12 लाख रुपये का ऋण लेकर डेयरी फार्म स्थापित किया था, लेकिन आवश्यक दस्तावेजों में कमी के कारण सब्सिडी स्वीकृत नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने बताया कि योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को दिया जा सकता है।आवेदन के साथ याचिकाकर्ता ने अपने नाम का वैध मूल निवासी प्रमाण पत्र

प्रस्तुत नहीं किया था। विभाग ने पहले ही उन्हें इस संबंध में पत्र जारी कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र का विकल्प नहीं हो सकता और उसे कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। पात्रता का निर्धारण निर्धारित नियमों के अनुसार होगा

अदालत ने कहा कि शासकीय योजनाओं में पात्रता का निर्धारण निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाएगा और इसके लिए तहसीलदार अथवा अधिसूचित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह विभाग के समक्ष अपना वैध मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे। इसके बाद संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवा, रायपुर कानून के अनुरूप उसके सब्सिडी दावे पर विचार कर दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर अंतिम निर्णय लें।

स्वास्थ्य मंत्री ने मेडलीपार द्वारा जांच प्रकिया को त्वरित करने दिए निर्देश

सीसीटीएनएस को और सशक्त बनाने डिप्टी सीएम शर्मा ने की उच्चस्तरीय बैठक

रायपुर। उप मुख्यमंत्री गृह विजय शर्मा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंगलवार को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि सीसीटीएनएस के माध्यम से न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को अधिक सुगम, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाया जाए। ई-एफआईआर से ई-फोरेंसिक तक सभी डिजिटल मॉड्यूल के प्रभावी संचालन पर जोर बैठक में ई-एफआईआर, ई-चालान, ई-साक्ष्य, मेडलीपार, ई-प्रिजन, ई-फोरेंसिक, सीआईएस, न्याय श्रुति तथा अन्य डिजिटल प्रणालियों को सीसीटीएनएस के साथ प्रभावी रूप से संचालित करने पर विस्तार से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी मॉड्यूलों के बीच समन्वय स्थापित कर न्याय प्रक्रिया को अधिक तेज और पारदर्शी बनाया जाए। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि राज्य के सभी जिलों में पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों को ई-साक्ष्य प्रणाली का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि डिजिटल साक्ष्यों का संकलन, संरक्षण एवं न्यायालय में प्रस्तुतिकरण पूरी दक्षता के साथ किया जा सके। बैठक में न्याय श्रुति प्रणाली को शीघ्र प्रारंभ करने पर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उच्च न्यायालय के माध्यम से सभी न्यायाधीशों की आवश्यक आईडी तैयार कराकर न्याय श्रुति प्रणाली को जल्द से जल्द गो-लाइव किया जाए, जिससे न्यायालयीन प्रक्रियाओं

में तकनीक का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रारंभिक चरण में दुर्ग, बिलासपुर तथा रायपुर कमिश्नरेट के सभी थानों में तथा राज्य के प्रत्येक जिले के दो-दो थानों में इस माह के अंत तक दो-दो ई-साइनिंग पैड उपलब्ध कराए जाएं। इससे शिकायतकर्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया सरल होगी और दस्तावेजों का ऑनलाइन निष्पादन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। इसके बाद पूरे राज्य में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। श्री शर्मा ने नवीन भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी पांचों स्तंभों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस, न्यायालय, जेल, फोरेंसिक तथा अभियोजन तंत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर न्याय प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जाए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेडिकल जांच एवं रिपोर्ट की प्रक्रिया को और तेज बनाने के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार कर सभी जिला अस्पतालों को मेडलीपार प्रणाली से जोड़ने तथा प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अगले तीन से चार महीनों के भीतर इस पूरी प्रणाली को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अधिकारियों से कहा कि वे राज्य में आकर ऑनबोर्डिंग के दौरान आ रही तकनीकी समस्याओं का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ समन्वय कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें, ताकि सीसीटीएनएस की सभी सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित हो सकें।

एफएसएल की कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश बैठक में उप मुख्यमंत्री ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की समीक्षा करते हुए सभी प्रकार के प्रकरणों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करने तथा जांच की समय-सीमा तय कर उसे न्यूनतम करने के निर्देश दिए। साथ ही फोरेंसिक विशेषज्ञों की आवश्यक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने तथा लंबित प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय कमी लाने पर विशेष जोर दिया।

अब सहकारी समितियों के जरिए किसानों को मिलेगी ड्रोन स्प्रेयर

रायपुर। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों को वैज्ञानिक खेती से जोड़ने की दिशा में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जिले की 5 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में %ड्रोन स्प्रेयर% सुविधा की आधिकारिक शुरुआत की गई है। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर इस महत्वाकांक्षी पहल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों ने बारिश की हल्की फुहारों के बीच ड्रोन स्प्रेयर का सफल प्रदर्शन किया। इस दौरान ड्रोन के माध्यम से उर्वरक और कीटनाशकों के सटीक छिड़काव, समय की बचत, कम लागत और बेहतर कृषि प्रबंधन की तकनीक को प्रदर्शित किया गया। समय और लागत की होगी बड़ी

बचतः मंत्री टंक राम वर्मासमारोह को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि आज का दिन जिले के कृषि इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जैसा है। ड्रोन तकनीक से कम समय में अधिक क्षेत्रफल में छिड़काव संभव होगा, जिससे रसायनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित होगा। साथ ही किसानों के श्रम और लागत में भारी कमी आएगी। खेतों में सीधे जाने की आवश्यकता न होने से फसलों को होने वाले नुकसान से भी बचाव होगा। उन्होंने आगे कहा कि ड्रोन दीदी पहल से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को कौशल विकास के साथ आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। रासायनिक खेती छोड़ प्राकृतिक व जैविक खेती अपनाएं किसानमंत्री श्री वर्मा ने रासायनिक रसायनों के दुष्प्रभावों पर चिंता जताते हुए किसानों से जैविक व प्राकृतिक खेती की ओर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी प्राचीन कृषि परंपराएं ही सतत (सस्टेनेबल) खेती का आधार हैं। जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और खाद्यान्न की गुणवत्ता में सुधार होता है इन 5 समितियों से मिलेगी ड्रोन की सुविधा‚द्यद्यभ ऋद्धड्डल - हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम में हुई शामिलजिले की बलौदाबाजार, कसडोल, बया, गिर्रा (पलारी) और दामाखेड़ा (सिमगा) सहकारी समितियों में फिलहाल 11 ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं।

इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बनी संयुक्त रणनीति

बीजापुर। वन्यजीवों के शिकार, लकड़ी तस्करी और अन्य वन अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के वन विभाग ने संयुक्त रणनीति तैयार की है। इसी कड़ी में सोमवार को इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर में तीनों राज्यों के वरिष्ठ वन अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई।बैठक वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप की मंशा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण पांडे और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) ओ.पी. यादव के निर्देश पर आयोजित की गई। इसमें सीमावर्ती वन क्षेत्रों में बढ़ते वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में वन्यजीवों के शिकार, लकड़ी तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए संयुक्त गश्त, एंटी-पोचिंग अभियान, डिजिटल इंटेलिजेंस नेटवर्क विकसित करने तथा रियल टाइम सूचना साझा करने पर सहमति बनी। साथ ही तीनों राज्यों के वन अमले के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि अंतरराज्यीय सहयोग से वन अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण और वनों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। बैठक में

पृथक पेंशन कार्यालय स्थापना के प्रस्ताव पर मांगा तत्काल प्रतिवेदन

रायपुर। प्रदेश के सभी संभागों एवं जिलों में पृथक पेंशन कार्यालय स्थापित करने की मांग पर शासन स्तर पर त्वरित कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने 10 जुलाई को मंत्रालय में मुख्य सचिव विकासशील से भेंट कर पेंशनर्स

हित से जुड़े विभिन्न विषयों के साथ पृथक पेंशन कार्यालय स्थापना की मांग का ज्ञापन सौंपा था। इसी ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए वित्त विभाग ने 17 जुलाई 2026 को संचालक, पेंशन एवं भविष्य निधि, रायपुर को पत्र जारी कर प्रदेश के सभी संभागों एवं जिलों में पृथक पेंशन कार्यालय स्थापित किए जाने के संबंध में तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग के अवर सचिव श्रीमती शांता खरे द्वारा जारी पत्र में इस विषय पर शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। महासंघ छत्तीसगढ़ के जे.पी. मिश्रा, एन.आर. साहू, बी.के. वर्मा, अनिल गोल्हानी, प्रवीण कुमार त्रिवेदी, टी पी सिंह, पी आर साहू,बी.एल. गजपाल, द्रौपदी यादव, आर.एन. ताटी, जे.पी. शुक्ला, लोचन पांडेय ,प्रदीप सोनी, माणिकचंद, डॉ शोषा सक्सेना,ओ.पी. भट्ट, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, भदौरिया, एस के धातोडे, एस.एन. देहारी, रूपकुमार झाड़ी, कासिमुद्दीन, आर.डी. झाड़ी, अरुण तिवारी, परमेश्वर स्वर्णकार, राकेश जैन, राजेंद्र कश्यप, कुंती राणा, उर्मिला शुक्ला,शैलेन्द्र सिन्हा, आर.जी. बोहरे, ओ.डी. शर्मा, सुहास लाम्बट, अभय शंकर गौराहा, बी एस दशमेर,गुरुचरण सिंह, अनिल पाठक, आर ए शर्मा, ठाकुर सुरेन्द्र सिंह,लता चावड़ा, आर के दीक्षित , एम एन पाठक, टी एल चंद्राकर, मालिक राम वर्मा, एम आर चंद्राकर, रमेश नंदे प्रेमचंद गुप्ता, सहित अनेक पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने इस त्वरित कार्यवाही के लिए मुख्य सचिव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आशा जताई है कि शीघ्र ही इस दिशा में ठोस निर्णय लिया जाएगा।

केंद्रीय विद्यालय ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ आरंग के नवीन भवन का उद्घाटन

आरंग। राष्ट्र निर्माण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्रीय विद्यालय, ग्रुप केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आरंग के नवीन भवन का उद्घाटन समारोह उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में शिक्षा, अनुशासन, संस्कार और उत्कृष्टता के नए अध्याय की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मध्य अंचल के विशेष महानिदेशक दीपक कुमार रहे। वहीं छत्तीसगढ़ सेक्टर के महानिरीक्षक शालिन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रुप केंद्र रायपुर के उपमहानिरीक्षक अजय कुमार सिंह ने की। उन्होंने अतिथियों का आत्मीय स्वागत करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की

जानकारी दी। समारोह का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत और पौधों के भेंट के साथ हुआ। स्वागत संबोधन में अजय कुमार सिंह ने केंद्रीय विद्यालय संगठन की पृष्ठभूमि और विद्यालय के विजन-मिशन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर 1963 को 20 रेजिमेंटल स्कूलों से शुरू हुआ केंद्रीय विद्यालय संगठन आज 1331 से अधिक विद्यालयों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण, मूल्यपरक और समावेशी शिक्षा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय आरंग में बालवाटिका-1 से 3 तथा कक्षा 1 से 5 तक कुल आठ कक्षाओं में करीब 320 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यालय के लिए ग्रुप केंद्र ष्टक्रक्कस्न आरंग द्वारा अस्थायी भवन, पेयजल, शौचालय और खेल मैदान सहित आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं नवीन स्थायी भवन के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी जारी है। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति, कला और राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का मंच संचालन केंद्रीय विद्यालय आरंग के शिक्षक प्रताप सोनी और लता गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। विद्यालय के प्राचार्य संजय कंसल ने अपने संबोधन में केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए ग्रुप केंद्र ष्टक्रक्कस्न के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान बालवाटिका-1 से कक्षा 5वीं तक के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उपहार और प्रोत्साहन सामग्री देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि दीपक कुमार ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में विद्यार्थियों को निरंतर परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्रसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

नेशनल लेवल पर राज्य को रिप्रेज़ेंट करेंगे

मावलंकर और ईस्ट ज़ोन शूटिंग चैंपियनशिप के तीन इवेंट्स में क्वालिफ़ाई किया

रायपुर. छत्तीसगढ़ पुलिस के निरीक्षक वैभव मिश्रा ने निशानेबाजी में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (द्गह्म्द्ब) के तत्वावधान में आयोजित चयन प्रक्रिया के तहत जी. वी. मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप और ईस्ट ज़ोन शूटिंग चैंपियनशिप-2026 के लिए तीन अलग-अलग स्पर्धाओं में क्वालिफाई किया है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ पुलिस के करीब 26 साल के इतिहास में पहली बार दर्ज हुई है।

नियमित अभ्यास से किया खुद को तैयार पुलिस सेवा की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने नियमित अभ्यास जारी रखा और सीमित समय में खुद को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। उनकी उपलब्धि यह संदेश देती है कि दृढ़

3 इवेंट में क्वालिफिकेशन

छत्तीसगढ़ राज्य राइफल एसोसिएशन की तरफ से आयोजित राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप-2026 में वैभव मिश्रा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में क्वालिफिकेशन हासिल किया। लगातार तीन इवेंट में चयन उनके तकनीकी कौशल और बेहतरीन प्रदर्शन का प्रमाण माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ का करेंगे प्रतिनिधित्व

अब वैभव मिश्रा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जी. वी. मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप और ईस्ट ज़ोन शूटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनकी इस उपलब्धि से पूरे पुलिस विभाग में उत्साह का माहौल है। अधिकारियों और सहकर्मियों ने उन्हें बधाई देते हुए इसे विभाग के लिए गर्व का क्षण बताया।

इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयास से कठिन लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं।

भारत व्यापार महोत्सव के लिए छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन शुरू

रायपुर. नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक होने वाले देश के सबसे बड़े ट्रेड फेयर भारत व्यापार महोत्सव के लिए छत्तीसगढ़ में बिजनेस डेलीगेट रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रायपुर स्थित कैट (द्गड्डह्ल) प्रदेश कार्यालय में इसके लिए बैठक आयोजित की गई। पहले ही दिन प्रदेश के कई व्यापारिक संगठनों और व्यापारियों ने उत्साह के साथ अपना पंजीयन कराया। बैठक में कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि इस बार महोत्सव में छत्तीसगढ़ की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी

जिलों से व्यापारी, उद्योगपति, स्टार्टअप और एमएसएमई प्रतिनिधि बड़ी संख्या में इस आयोजन में शामिल होंगे। अमर पारवानी ने बताया कि भारत व्यापार महोत्सव सिर्फ प्रदर्शनी नहीं, बल्कि देशभर के व्यापार और उद्योग जगत का बड़ा मंच है। यहां उद्योगपति, निर्माता, वितरक, आयात-निर्यात से जुड़े कारोबारी, निवेशक और स्टार्टअप एक साथ आएंगे। इससे नए व्यापारिक संबंध बनाने और कारोबार बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। महोत्सव में शामिल होने वाले व्यापारियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस नेटवर्किंग, बी-टू-बी बैठकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), नई तकनीकों, डिजिटल बिजनेस, आयात-निर्यात और वैश्विक बाजार की जानकारी मिलेगी। साथ ही उद्योग विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से सीधे संवाद का अवसर भी मिलेगा। कैट के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन ने कहा कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ के व्यापारियों, उद्यमियों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अच्छा मौका है।

भारत के उभरते ट्रिपल जंपर सेल्वा राष्ट्रमंडल खेलों में पदर्पण को लेकर हैं उत्साहित

ग्लासगो। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से शुरू होने जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के उभरते हुए ट्रिपल जंपर सेल्वा प्रभु पदार्पण के लिए पूरी तरह तैयार होने के साथ ही उत्साहित भी हैं।

सेल्वा ने पिछले कुल समय में अच्छे प्रदर्शन से अपने को साबित किया है। इसी कारण उन्हें भारतीय दल में जगह मिली है। सेल्वा भी अपने करियर के सबसे बड़े मंचों में से एक पर देश का प्रतिनिधित्व करने को लेकर उत्साहित है। सेल्वा ने कहा कि उन्हें इसी दिन का इंतजार है जब वह भारतीय जर्सी पहनेंगे। उनका लक्ष्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, और दुनिया के बेहतरीन एथलीटों का मुकाबला करना है। सेल्वा के अनुसार अमेरिका में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी एनसीएए सर्किट में बिताए गए पिछले कुछ साल का अनुभव उनके लिए यहां लाभदायक रहेगा। उन्होंने कहा कि एनसीएए में मुकाबला करने से उन्हें हर पहलू में आगे बढ़ने में मदद मिली है। वहां प्रतियोगिता का स्तर बहुत ऊंचा है, जिसने उन्हें तकनीकी, शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। सर्वश्रेष्ठ कोचों के साथ प्रशिक्षण और हर हफ्ते विश्व स्तरीय एथलीटों के खिलाफ मुकाबला करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए वह उत्मविश्वास से भरे हुए हैं। सेल्वा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रदर्शन में निरंतरता पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। उनका मुख्य लक्ष्य अपनी गति, लय और तकनीक को बेहतर बनाने पर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों के ट्रिपल जंप का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे सेल्वा एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। वे बहुत आगे की सोचने के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनका लक्ष्य आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करना है। उन्हें विश्वास है कि यदि वे अपने जंप सही तरीके से कर पाते हैं, तो वे अच्छा परिणाम ला सकते हैं। भारत के एथलेटिक्स दल के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के बीच, सेल्वा की नजर अपने वर्षों के निरंतर प्रदर्शन को सीनियर मल्टी-स्पोर्ट गेम्स में एक यादगार पदार्पण में बदलने पर होगी, जिससे देश को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं।

दिलीप ट्रॉफी अगले माह शुरू होगी, रुतुराज करेंगे वेस्ट जोन की कप्तानी

मुम्बई। बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ अगले माह शुरू होने वाले घरेलू टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन की कप्तानी करेंगे। वहीं बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर शम्स मुलानी टीम के उप-कप्तान होंगे। दिलीप ट्राफी मुकाबले 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) मैदान पर खेले जाएंगे। इसमे देश भर के उभरते हुए क्रिकेटर खेलते नजर आयेंगे।

पिछले साल वेस्ट जोन की कप्तानी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने की थी और टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। हालांकि, सेंट्रल जोन से पहली पारी की बढ़त के कारण वे फाइनल में जगह नहीं बना पाए थे। इस बार कप्तानी कर रहे रुतुराज का लक्ष्य टीम को जीत दिलाना रहेगा। गायकवाड़ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के कप्तान रहे हैं। वह भारत ए टीम के भी कप्तान रहे हैं। उनकी कप्तानी के अनुभव से वेस्ट जोन को लाभ होगा।

टीम में गायकवाड़ के अलावा, विस्फोटक सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ, के अलावा सरफरार खान और उनके भाई मुशीर भी शामिल हैं। इसके अलावा टीम में जयमीत पटेल और शिवालिक शर्मा को भी रखा गया है। वहीं गेंदबाजी विभाग की कमान मुलानी के पास रहेगी। जिन्हें ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर तनुष कोटियन और बाएं हाथ के स्पिनर सिद्धार्थ देसाई का साथ मिलेगा। तेज गेंदबाज के तौर पर अनुभवी शार्दुल ठाकुर के अलावा तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी और ऑलराउंडर अतीत सेठ भी शामिल हैं। टीम में दो विशेषज्ञ विकेटकीपर हार्विक देसाई और उर्विल पटेल भी शामिल हैं। इस प्रकार देखा जाये तो ये टीम अनुभवी और युवा खिलाड़ियों से भरी हुई है।

अश्विन बोले, कैमरे के सामने कोई भी अपनी खराब छवि नहीं दिखाना चाहता

चेन्नई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने ड्रेसिंग रूम के माहौल पर प्रकाश डाला है। अश्विन ने कहा कि कैमरे के सामने कोई भी खिलाड़ी या कोच अपनी खराब छवि पेश नहीं करना चाहता है। यह एक तरह का नो ड्रामा जोन होता है, जहां हर कोई पेशेवर दिखना चाहता है। यानी, ड्रेसिंग रूम के भीतर खिलाड़ियों और मुख्य कोच के बीच मतभेद हो सकते हैं, मनमुटाव भी संभव है पर जैसे ही वे कैमरे के सामने आते हैं, वे ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक है और टीम एकजुट है। यह पेशेवर माहौल का एक अभिन्न अंग है, जहां आंतरिक संघर्षों को निजी रखा जाता है और बाहरी दुनिया के लिए एक सामंजस्यपूर्ण तस्वीर पेश की जाती है।

भारतीय टीम को हाल में आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर मिली करारी हार के बाद टीम के अंदर के माहौल पर सवाल उठने स्वाभाविक थे। आयरलैंड से टी20 सीरीज में 2-0 से हारने और इंग्लैंड में टी20 व एकदिवसीय दोनों सीरीज गंवाने के बाद टीम पर काफी दबाव था। ऐसे में, खिलाड़ियों और कोच का बाहरी तौर पर एकजुट दिखना और कैमरे के सामने नो ड्रामा की नीति अपनाना टीम की एकता और प्रदर्शन के महत्व को दशार्ता है, भले ही पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और हो। अश्विन के शब्दों ने क्रिकेट के ग्लैमरस पर्दे के पीछे की उस हकीकत को उजागर किया है, जहाँ निजी मनमुटावों को पेशेवर गरिमा के तले दबाकर रखा जाता है और सिर्फ प्रदर्शन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है।

पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के नाम है एक अनोखा रिकार्ड

मुम्बई। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान अपने दौर के एक बेहतरीन बल्लेबाज रहे है। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के साथ सलामी जोड़ीदार के तौर पर उन्होंने कई बड़े साझेदारियां बनायी हैं। वह बदकिस्मती से एक भी शतक नहीं लगा पाये पर इसके बाद भी उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 2000 से अधिक रन है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चेतन ने अपनी क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 2084 रन बनाए, जबकि 7 एकदिवसीय मैचों में 153 रन बनाये। उनकी बल्लेबाजी की अनूठी बात यह थी कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कभी शतक नहीं लगा पाए। कई मौकों पर वह शतक के बेहद करीब आकर भी पूरा नहीं कर पाये। वह 9 बार 80 से 97 के बीच के स्कोर पर आउट हुए। वह टेस्ट क्रिकेट में बिना शतक लगाए 2000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, ये अपने आप में एक अनोखा और अविश्वसनीय रिकॉर्ड था। इस बल्लेबाज ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 179 मैच खेले और 40 की प्रभावशाली औसत से 11,143 रन बनाए, जिसमें 21 शानदार शतक और 59 अर्धशतक शामिल थे। घरेलू सर्किट में उनके लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 1978 में भारतीय टीम में जगह मिली जहां वह गावस्कर के सलामी जोड़ीदार के तौर पर उतरे। इस बल्लेबज ने साल 1981 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपने साथी सलामी बल्लेबाज और तत्कालीन कप्तान सुनील गावस्कर को पांच साल के प्रतिबंध से भी बचाया था। अगर वह नहीं बचाते तो गावस्कर का करियर समाप्त होना तय था। हालांकि उनको उस घटना के लिए याद किया जाता है जो 1981 में मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट मैच के दौरान हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनिस लिली की एक गेंद पर अंपायर ने गावस्कर को एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया। गावस्कर अंपायर के इस फैसले से इतने नाराज और असहमत थे कि उन्होंने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और गावस्कर गुस्से में अपने सलामी जोड़ीदार चेतन चौहान का हाथ पकड़कर मैदान से बाहर जाने लगे, मानो वह मैच का बहिष्कार करना चाहते हों।

भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देने तैयार हैं जिम्बाब्वे : रजा

हरारे। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने भारतीय क्रिकेट टीम को चुनौती देते हुए कहा है कि वे हमें कमजोर समझने की भूल न करें। हमारी टीम टी20 विश्वकप विजेता भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देने तैयार है।

माना जा रहा है कि हाल में जिस प्रकार से भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। उससे रजा कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं। उन्होंने कह कि हमारी टीम के पास जीत की तय योजना है। ऐसे में अगर भारतीय टीम ने उन्हें हल्के में लिया तो उसे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कप्तान रजा ने कह कि आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज में कोई एकतरफा मुकाबला नहीं होगा, बल्कि दोनों टीमों के पास सीरीज जीतने का पूरा मौका होगा। जिम्बाब्वे इस सीरीज को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रहा है,

रजा ने कहा, दोनों देशों को इस सीरीज में बराबर मौका मिलेगा। लेकिन एक बात मैं बहुत

निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिम्बाब्वे आजकल बहुत बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह सीरीज बहुत रोमांचक होगी। उन्होंने अपनी टीम के हालिया प्रदर्शन का भी जिक्र किया, जिसमें फरवरी में कोलंबो में आईसीसी टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराकर सनसनी फैलाना शामिल है, जिसने ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। जिम्बाब्वे ने इस साल श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ भी महत्वपूर्ण जीत हासिल की हैं, जो उनके आत्मविश्वास का मुख्य कारण है।

25 और 26 जुलाई को खेला जायेगा तीसरा मैच

रजा ने भारतीय टीम की बदलाव के दौर से गुजरने वाली स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हां, भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है और कुछ हद तक जिम्बाब्वे में भी थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मैं इसे एकतरफा सीरीज के रूप में नहीं देखता। यह बयान साफ करता है कि जिम्बाब्वे भारत की वर्तमान कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 23 जुलाई सेशुरू हो रही है, जिसमें दूसरा और तीसरा मैच 25 और 26 जुलाई को उसी स्थान पर खेला जाएगा।

कारोबार

लावा अपनी विराट वी 1 सीरीज को भारत में जल्द करेगी लांच

नई दिल्ली। स्मार्टफोन निमार्ता कंपनी लावा अपनी बहुप्रतीक्षित विराट वी 1 सीरीज को जल्द लॉन्च करने जा रही है।

ग्राहकों को इस सीरीज में कम बजट में शानदार फीचर्स मिलने वाले हैं। इस सीरीज में लावा विराट वी1 5जी और लावा विराट वी1 4जीमॉडल शामिल होंगे, जिन्हें कम बजट में शानदार फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा।

लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इन दोनों स्मार्टफोन के कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स की पुष्टि कर दी है, जिनमें 120एचझेड डिस्प्ले, एआई कैमरा, आईपी64 रेटिंग और दमदार बैटरी शामिल हैं। ये स्मार्टफोन विशेष रूप से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। दोनों स्मार्टफोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जो 120एचझेड रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव बेहद स्मूथ रहेगा।

धूल और हल्के पानी के छींटों से सुरक्षा के लिए इनमें आईपी64 रेटिंग दी गई है। सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी मिलेगा।

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए दोनों फोन में 13एमपी का एआई डुअल रियर कैमरा और सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 5एमपी का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कंपनी ने वर्चुअल रैम फीचर भी शामिल किया है, जो जरूरत पड़ने पर फोन की रैम को बढ़ाने में मदद करेगा। लावा विराट वी1 5जी में यूनिसोक टी8200 प्रोसेसर, 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज मिलेगी, जबकि इसकी सबसे बड़ी खासियत 6000 एमएएच की विशाल बैटरी होगी जो लंबे समय तक साथ निभाने का दावा करती है। वहीं, लावा विराट वी1 4जी में यूनिसोक एससी9863ए प्रोसेसर, 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज के साथ 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है।

आसुस का नया आसुस पीएडी भारत में लांच

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में आसुस कंपनी ने फिर टैबलेट सेगमेंट में वापसी करते हुए नया आसुस पीएडी लॉन्च किया है। कंपनी ने फिलहाल इस टैबलेट की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन आसुस पीएडी की बिक्री 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे फ्लिपकार्ट, आसुस ई-शॉप, आसुस और आरओजी स्टोर्स, रिलायंस डिजिटल और कंपनी के अधिकृत रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा। यह टैबलेट छात्रों, पेशेवरों और मनोरंजन पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें एक बड़ी ओलेड स्क्रीन, शक्तिशाली प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ जैसे कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

आसुस पीएडी में 12.2 इंच का 2.8के ओलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144एचझेड है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स तक जाती है, जिससे तेज धूप में भी कंटेंट आसानी से देखा जा सकता है। टीयूवी सर्टिफिकेशन के साथ, कंपनी का दावा है कि यह डिस्प्ले आंखों पर कम दबाव डालता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8300 प्रोसेसर दिया गया है, जो 8जीबी एलपीडीडीआर5एक्स रैम और 128जीबी या 256जीबी स्टोरेज विकल्पों के साथ आता है। जरूरत पड़ने पर माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 1टीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

बेहतर ऑडियो अनुभव के लिए डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले चार स्पीकर दिए गए हैं, जबकि कनेक्टिविटी के लिए वायफाय 6ई, ब्लूटूथ 5.3 और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। आसुस इस टैबलेट के साथ प्रोटेक्टिव फोलियो केस भी दे रही है और यह आसुस पीईएस 2.0, ब्लूटूथ कीबोर्ड, गूगल सर्कल टू सर्च और आसुस ग्लाइडेक्स जैसे फीचर्स को भी सपोर्ट करता है।

यह टैबलेट नवीनतम एंड्रॉयड 16 पर चलता है और इसमें 9000एमएएच की दमदार बैटरी दी गई है, जो 45वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और लगभग 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है। फोटोग्राफी के लिए आसुस पेड में 13एमपी का रियर कैमरा और 5एमपी का फ्रंट कैमरा मिलता है, साथ ही वीडियो कॉलिंग के लिए फेस अनलॉक सपोर्ट भी है।

ऐपल की मैकबुक और आईपैड पर मुफ्त एक्सेसरीज का ऑफर

नई दिल्ली। भारत में ऐपल ने अपनी बहुप्रतीक्षित बैक टू स्कूल सेल 2026 शुरू कर दी है। कंपनी इस सेल में छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े अन्य पेशेवरों के लिए शानदार डील्स और मुफ्त उपहार लेकर आई है। इस सेल में मैकबुक, आईपैड और मैकबुक नियो जैसे ऐपल उत्पादों पर एजुकेशन डिस्काउंट के साथ मुफ्त एयरपॉड्स, ऐपल पेंसिल प्रो और एयरटैग्स जैसे आकर्षक उपहार मिल रहे हैं। यह सेल 27 अगस्त तक चलेगी। यह उन सभी के लिए एक शानदार अवसर है जो नया ऐपल डिवाइस खरीदने की योजना बना रहे हैं।

इस ऑफर का लाभ केवल कॉलेज के छात्र ही नहीं, बल्कि स्कूल या कॉलेज के शिक्षक, स्टाफ और अपने बच्चों के लिए ऐपल डिवाइस खरीदने वाले माता-पिता भी एजुकेशन स्टोर के माध्यम से उठा सकते हैं। अगर आप नया मैकबुक एयर एम5 खरीदते हैं, जिसकी शुरूआती कीमत रुपए 1,37,900 है, तो आपको मुफ्त एयरपॉड्स 4 या 4 एयरटैग्स का पैक चुनने का विकल्प मिलेगा। ग्राहक थोड़ी अतिरिक्त राशि देकर एयरपॉड्स 4 को सिर्फ रूपए 5,000 में या एयरपॉड्स प्रो 3 को सिर्फ रूपए 13,000 में अपग्रेड भी कर सकते हैं। मैकबुक प्रो के सभी मॉडल, जिनमें एम5, एम5 प्रो और एम5 मैक्स शामिल हैं, भी इस ऑफर के दायरे में आते हैं और उनके साथ भी मुफ्त एयरपॉड्स 4 या एयरटैग्स का विकल्प उपलब्ध है। आईपैड खरीदने वालों के लिए भी ऐपल ने खास पेशकश की है। आईपैड एयर (एम4) जिसकी शुरूआती कीमत रुपए 83,900 है, और 2025 आईपैड प्रो जिसकी शुरूआती कीमत रुपए 1,27,900 है, इन दोनों के साथ ऐपल पेंसिल प्रो बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। इसके अलावा, ऐपल का नया मैकबुक नियो भी इस सेल का हिस्सा है, जिसके 256जीबी मॉडल पर रुपए 69,900 और 512जीबी (टच आईडी) मॉडल पर रुपए 79,900 की प्रभावी कीमत के साथ लगभग रुपए 10,000 तक की बचत हो रही है।

सर्राफा बाजार में जबरदस्त उछाल, सोना खरीदना हुआ महंगा

नई दिल्ली। भारतीय सराफा बाजार में पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट देखने को मिली. लेकिन इस सप्ताह सराफा बाजार में हर दिन उछाल देखने को मिल रहा है.

सोमवार के बाद मंगलवार को भी बाजार की शुरूआत उछाल के साथ हुई. शुरूआती कारोबार में ही सोना 900 रुपये से ज्यादा के उछाल के साथ कारोबार करता दिखा. जबकि चांदी का भाव 2600 रुपये चढ़ गया. बुलियंस डॉट को डॉट इन वेबसाइट से प्राप्त डेटा के मुताबिक, मंगलवार (21 जुलाई) सुबह 9.50 बजे सोना 950 रुपये और चांदी 2630 रुपये चढ़कर कारोबार करती दिखी. मंगलवार को सराफा बाजार में आई तेजी के बाद 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 131,065 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गईं. जबकि 24 कैरेट गोल्ड का भाव 142,980 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं चांदी का भाव 221,230 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है.

एमसीएक्स और विदेशी बाजार में कीमत

वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (टउ) पर सोना 957 रुपये यानी 0.68 प्रतिशत के उछाल के साथ 142,345 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. जबकि चांदी का भाव यहां 2373 रुपये यानी 1.09 प्रतिशत चढ़कर 220,773 रुपये प्रति किग्रा पर पहुंच गया. वहीं विदेशी बाजार यानी यूएस कॉमेक्स पर सोना 37.70 डॉलर यानी 0.94 प्रतिशत महंगा होकर 4053.60 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. जबकि चांदी का भाव यहां 1.06 डॉलर या 1.85 प्रतिशत तेजी के साथ 58.13 डॉलर प्रति औंस हो गया है.

411 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश, फिर भी 1,631 करोड़ का कर्ज

नई दिल्ली। कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स ने FY26 में 411 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश कमाया, जो कंपनी के इतिहास का सबसे अच्छा साल था. फिर उसी साल कंपनी पर 366 करोड़ का और कर्ज चढ़ गया. अप्रैल 2026 के आखिर तक उसका कर्ज बढ़कर 1,631 करोड़ हो गया, जबकि उसके पास कैश सिर्फ 7 करोड़ था. और अब यही कंपनी पब्लिक इंवेस्टर्स से 450 करोड़ जुटाना चाहती है, अपनी कमाई के 17 गुना वैल्यूएशन पर. असल में, कंपनी के कामकाज का बिजनेस मजबूत है. कैलिबर, कोल इंडिया के लिए कोयले की माइनिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करती है. कोल इंडिया हर साल अपने प्रोडक्शन का ज्यादा हिस्सा आउटसोर्स कर रही है. पिछले 2 सालों में रेवेन्यू सालाना लगभग 33% की दर से बढ़ा है, और ऑर्डर बुक FY26 के अनुमानित रेवेन्यू से लगभग 6 गुना है.

महत्वपूर्ण ख़बर

अंतर्राज्यीय बर्ड ट्रेड गिरोह की महिला तस्कर गिरफ्तार

■ भोपाल। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ), मध्यप्रदेश की इंदौर इकाई ने वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध अभियान में लगातार सफलता प्राप्त करते हुए अंतर्राज्यीय बर्ड ट्रेड गिरोह की 9वीं मुख्य आरोपी सविताबेन (पति : विनोद दंतानी, निवासी अहमदाबाद, गुजरात) को गिरफ्तार किया है।

आरोपी पिछले तीन वर्षों से फरार चल रही थी। सविता बेन को 20 जुलाई 2026 को इंदौर में गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि गिरोह मध्यप्रदेश से संरक्षित प्रजाति के पक्षियों (तोतों) का अवैध परिवहन कर उन्हें गुजरात के विभिन्न शहरों में ऊंचे दामों पर बेचता था।

विशेष न्यायालय, इंदौर में प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। प्रकरण की विस्तृत विवेचना जारी है। बर्ड- ट्रेड गिरोह के विरुद्ध जारी कार्रवाइयों की श्रृंखला में 20 जुलाई 2026 को के 8वें आरोपी अहमदाबाद निवासी आशीष को गिरफ्तार किया गया था।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी गारंटी

■ भोपाल। मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केवल खाद्यान्न वितरण की योजना नहीं, बल्कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का संवैधानिक आधार प्रदान करने वाला सामाजिक न्याय का सशक्त माध्यम है।

प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "गरीब कल्याण" के संकल्प और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य का कोई भी पात्र परिवार खाद्यान्न के अधिकार से वंचित न रहे और भूखा न सोए।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष

एमपी विधानसभा में कांग्रेस का काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन, सदन में जमकर हंगामा

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक दल ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा परिसर और सदन के भीतर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां लेकर सदन पहुंचे और विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने नीट परीक्षा और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की।

कार्यवाही हुई प्रभावित

हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय तक प्रभावित रही। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार जवाबदेही से बच रही है, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के प्रदर्शन को राजनीतिक बताया। मानसून सत्र के दौरान शिक्षा और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

मप्र में 2008 के बाद की शादियों का पंजीयन न कराने पर 25,000 रुपये जुर्माना

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश यूसीसी बिल पास करने वाला चौथा भाजपा शासित राज्य बन गया है। अब इस विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

इस कानून में बहुविवाह, ट्रिपल तलाक, हलाला और लिव-इन रिलेशनशिप पर रोक जैसे प्रमुख प्रावधानों के अलावा आम नागरिकों के विवाह, नौकरी, संपत्ति और राज्य से बाहर निवास करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण व्यावहारिक नियम शामिल किए गए हैं।

यूसीसी से जुड़ी 4 बड़ी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी हैं:

1. विवाह पंजीयन: 23 सितंबर 2008 के बाद की शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

अनिवार्य पंजीयन: 23 सितंबर 2008 से यूसीसी लागू होने की तिथि तक हुई ऐसी सभी शादियां जिनका अभी तक पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) नहीं हुआ है, उन्हें कानून लागू होने के एक साल के भीतर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा।

2008 से पहले की शादियां: 2008 से पहले हुई शादियों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा।

यदि तय समय में पंजीयन नहीं कराया जाता है, तो रजिस्ट्रार नोटिस जारी कर सकता है। इसके बाद भी पंजीयन न कराने पर 25,000 रुपये तक का जुमार्ना और अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि, केवल पंजीयन न होने से शादी अवैध नहीं मानी जाएगी।

2. नौकरी: बिना यूसीसी सर्टिफिकेट रिकॉर्ड में बदलाव नहीं

सेवा रिकॉर्ड में बदलाव: यूसीसी की धारा 21 के अनुसार, कोई भी सरकारी या निजी नियोक्ता अपने कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में वैवाहिक स्थिति में बदलाव तभी करेगा, जब वह यूसीसी के तहत जारी विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

मान्य दस्तावेज: शादी के बाद अब सिर्फ शादी का कार्ड, हलफनामा या अन्य दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। पति या पत्नी का नाम जोड़ने अथवा वैवाहिक स्थिति बदलने के लिए यूसीसी मैरिज सर्टिफिकेट ही अनिवार्य होगा।

3. संपत्ति विवाद: कोर्ट नियुक्त कर सकेगा 'रक्षक'

यदि किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसकी संपत्ति पर विवाद होता है या गलत कब्जे/दुरुपयोग की आशंका होती है, तो अदालत रक्षक (प्रोटेक्टर) नियुक्त कर सकेगी। यह रक्षक कोर्ट की निगरानी में संपत्ति का कब्जा लेकर उसकी सूची तैयार करेगा और मेंटेनेंस का इंतजाम करेगा।

4. राज्य से बाहर रहने वालों पर भी लागू होंगे नियम

यूसीसी कानून उन लोगों पर भी लागू होगा जो वर्तमान में नौकरी, पढ़ाई या कारोबार के सिलसिले में मध्य प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, लेकिन कानूनन मप्र के स्थायी निवासी हैं। मप्र का निवासी उन्हें माना जाएगा जो राज्य में रहते हों, राज्य/केंद्र सरकार के मप्र में पदस्थ कर्मचारी हों, अथवा मप्र में जन्मे व्यक्ति जिनके माता-पिता यहां के निवासी हों या अचल संपत्ति रखते हों। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा भरोसा

जबलपुर की ओएफके में तैयार होंगे स्वदेशी हाईटेक हथियार

जबलपुर। जबलपुर स्थित आर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया (ओएफके) अब भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने वाले स्वदेशी और अत्याधुनिक सैन्य साजो-सामान का बड़ा उत्पादन केंद्र बनने जा रही है।

ऑपरेशन सिंदूर में एल-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन के प्रभावी प्रदर्शन के बाद इसके उत्पादन को नई गति दी जाएगी। इसके साथ ही 120, 220, 450 किलोग्राम और थाउजेंड पाउंडर बमों की नई खेप भी यहीं तैयार होगी।

श्रमिक सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित उत्पादन में राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों के लिए 500 और 1000 किलोग्राम के स्वदेशी जनरल पर्पस एरियल बम, बंकर और बख्तरबंद ठिकानों को ध्वस्त करने वाले 250 किलोग्राम बम तथा आधुनिक टैंकों के लिए 125 मिमी एफएसएपीडीएस टैंकभेदी गोला-बारूद शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी नई मजबूती

इससे न केवल सेना की युद्ध क्षमता मजबूत होगी, बल्कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी नई मजबूती मिलेगी।

एक नजर में

- एल-70 का उत्पादन फिर होगा तेज।
- 120, 220, 450 किग्रा और थाउजेंड पाउंडर बम बनेंगे।
- 500 व 1000 किग्रा जीपी एरियल बम राफेल-जगुआर के लिए।
- 250 किग्रा बम बंकर और सैन्य वाहनों पर असरदार।
- 125 मिमी एफएसएपीडीएस टैंकभेदी गोला-बारूद भी होगा तैयार।
- आत्मनिर्भर भारत के रक्षा उत्पादन को मिलेगा बड़ा बल।

कूनो नेशनल पार्क के गेट बंद होने के बाद भी हो रहा चीतों का दीदार

19 में से नौ बाहर घूम रहे

श्योपुर। मानसून के तीन महीनों के लिए कूनो नेशनल पार्क के गेट बंद कर दिए गए हैं लेकिन स्थानीय लोगों को चीतों का दीदार करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही। क्योंकि चीते अब कूनो के जंगल से निकलकर रहवासी इलाकों, खेतों और सड़कों पर घूमते हुए देखे जा रहे हैं।

बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में इस समय कुल 49 चीते हैं, इनमें से 19 चीते तो खुले जंगल में घूम रहे हैं। जबकि नौ चीते गांवों के आसपास शिकार करते अथवा दौड़ते भागते दिख जाते हैं। हाल ही में दो चीतों को वीरपुर तहसील के कूनो सायफन पुल के पास देखा गया था। श्योपुर और बड़ौदा क्षेत्र में भी चीतों की मौजूदगी की सूचना मिली है। विजयपुर, अगरा, शिवपुरी, ग्वालियर और राजस्थान के भीलवाड़ा से लेकर सवाईमाधौपुर तक चीतों के देखे जाने की घटनाएं बढ़ी हैं।

कराहल क्षेत्र में भी चीतों ने बछड़ों का शिकार किया था। अच्छी बात यह है कि पिछले तीन वर्षों में चीतों द्वारा इंसानों पर हमले की कोई घटना नहीं हुई। हालांकि पालतू जानवरों के शिकार से पशुपालकों में नाराजगी है। ऐसी स्थिति में पशुपालकों को मुआवजा देने का प्रविधान भी है।

इस संबंध में कूनो नेशनल पार्क के डीएफ ओ आर. थिरुकुराल ने बताया कि खुले जंगल में 19 चीते हैं, बाकी बाड़े में हैं। कूनो से बाहर कितने चीते हैं यह तो नहीं बता सकता लेकिन वह जहां भी हैं सुरक्षित और स्वस्थ हैं। उन पर हमारी ट्रेकिंग टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं।

डॉ. हेडगेवार ने दिया था समानता का विचार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

रविंद्र भवन में हुआ डॉ. हेडगेवार के जीवन और कार्यों पर केंद्रित महानाट्य का मंचन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने देशभक्ति के साथ समानता का दर्शन दिया था। वे भारत माता को मिलने जा रही स्वतंत्रता को कायम रखने के महत्व को पहले ही जान चुके थे, इस नाते उन्होंने राष्ट्र हित में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। वे दूरदर्शी सोच के साथ रचनात्मक प्रकल्प संचालित करते थे। डॉ. हेडगेवार के समता के भाव को आज राष्ट्र भी अंगीकार कर रहा है। समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल भी इस भाव को दृष्टिगत रखते हुए की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रवींद्र भवन में संस्कार भारती द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष होने के अवसर पर हुए महानाट्य ₹युग प्रवर्तक डॉ. हेडगेवार₹ के मंचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ईश्वर विशेष कार्य के लिए कोई निमित्त ढूंढता है। स्वामी विवेकानंद की ये भविष्यवाणी कि आने वाली सदी भारत की होगी, आज चरितार्थ हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, डॉ. हेडगेवार जी की कल्पना के भारत के निर्माण में संलग्न हैं। राष्ट्र अपने गर्व और गौरव को प्राप्त कर रहा है।भारत की पहचान एक विधान है।हमारा मूल

दर्शन समानता का है। डॉ. हेडगेवार ने स्वतंत्रता के पहले चुनौती भरे दौर में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सर्वोपरि के भाव का प्रकटीकरण ही नहीं किया,लाखों लाख नागरिकों को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संस्कार भारती को डॉ. हेडगेवार के योगदान को नाटक के माध्यम से मंचित किये जाने के लिए बधाई दी। प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मध्यप्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने का उल्लेख करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम को राष्ट्रीय सेवक संघ के पदाधिकारी श्री हेमंत मुक्तिबोध ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्र को वैभव की ओर ले जाने के भरसक प्रयास किए। यह नाटक उनके जीवन के समर्पण,राष्ट्र निष्ठा और कर्म आधारित जीवन के स्वरूप को सामने लाने का माध्यम है। इस अवसर पर मंच पर वरिष्ठ पदाधिकारी श्री अशोक पांडे, , फिल्म अभिनेता और रंगमंच निर्देशक श्री राजीव वर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम में श्री शशि भाई सेठ, पूर्व राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी, सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, संस्कृति संचालक श्री एन.पी. नामदेव और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत किया गया। आभार प्रदर्शन श्री रविंद्र सहस्त्रबुद्धे ने किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नाटक के कलाकारों को उत्कृष्ट अभिनय के लिए बधाई दी। नागपुर की नादब्रम्ह संस्था द्वारा तैयार इस नाटक का निर्देशन श्री सुबोध सुरजीकर ने किया। नाटक के लेखक डॉ. अजय प्रधान हैं। संस्कृति विभाग मध्यप्रदेश शासन के सहयोग से हुए नाटक में दक्ष कलाकारों ने प्रभावी अभिनय कर नाट्य प्रस्तुति को सफल बनाया। देश के अनेक नगरों में नाटक का मंचन हुआ है।

मध्यप्रदेश की धरती पर निवेशकों का स्वागत : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। प्रसन्नता व्यक्त की है कि उद्योगपति और निवेशक प्रदेश में निवेश करने में रूचि दर्शा रहे है। उन्होंने कहा कि समृद्धशाली देश के दिल में निवेश करने के इच्छुक प्रत्येक निवेशक का दिल से स्वागत है। मुख्यमंत्री से मंगलवार को मप्र विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में श्याम सेल एंड पावर कम्पनी लिमिटेड के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। कम्पनी के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं चीफ आपरेटिंग आफिसर श्री दीपक कुमार गौर ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अपनी कम्पनी की भावी परियोजनाओं की जानकारी दी। पॉवर कंपनी के निवेशकों ने बताया कि उनकी कंपनी स्टेनलेस स्टील बनाती है। धार जिले के औद्योगिक प्रक्षेत्र पीथमपुर में उनकी एक निर्माण इकाई पहले से ही संचालित है। इस निर्माण इकाई में कंपनी ने 550 करोड़ रुपए का निवेश कर 1300 लोगों को रोजगार दिया है। कंपनी पीथमपुर में ही अपनी दूसरी उत्पादन इकाई प्रारंभ करना चाहती है। कंपनी इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर 1000 हजार से अधिक लोगों को रोजगार देने की मंशा रखती है। इसके लिए उन्हें पीथमपुर में ही अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। कंपनी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से उन्हें अतिरिक्त भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया। प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि कम्पनी को प्रदेश की सभी नवीन औद्योगिक नीतियों की जानकारी दी गई है।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सख्ती, लापरवाही पर नोटिस एवं ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई के निर्देश

मुख्य अभियंताओं के सात दलों ने 35 निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण, उत्कृष्ट कार्यों की सराहना

भोपाल। प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई औचक निरीक्षण व्यवस्था अंतर्गत 20 जुलाई को मुख्य अभियंताओं के सात दलों द्वारा भोपाल, जबलपुर, गुना, इंदौर, सीधी, उज्जैन एवं छतरपुर जिलों में 35 निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री भरत यादव की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की गई।

समीक्षा के दौरान श्री भरत यादव ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने के निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गुना जिले में मावन-पिपरिया सड़क निर्माण कार्य तथा उज्जैन जिले में डोंगला-लासुडिया श्रीपथ सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा संबंधित निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार गुना में निमार्णाधीन खेल परिसर के कार्य में कमियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने एवं संबंधित कंसल्टेंट को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए।

भोपाल संभाग के बरखेड़ी देव परिक्रमा मार्ग पर सड़क सुरक्षा संबंधी कमियां पाए जाने पर संभावित दुर्घटना स्थलों पर तत्काल क्रैश बैरियर लगाने तथा प्रदेश के अन्य संवेदनशील स्थलों पर भी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान 19 अन्य निर्माण कार्यों में पाई गई कमियों के निराकरण के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

उत्कृष्ट कार्य की सराहना

इंदौर जिले में निमार्णाधीन 250 सीटर कन्या छात्रावास का कार्य उत्कृष्ट गुणवत्ता का पाए जाने पर कार्यपालन यंत्री श्रीमती आरती यादव, सहायक यंत्री श्री राजेश मकवाने एवं उपयंत्री श्री जितेन्द्र भल्ला की सराहना की गई। बैठक में सभी अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुरूप समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने, पुल-पुलियों के मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता देने, जर्जर पुलों के नए निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं नियमित निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

मध्यप्रदेश पुलिस का नशे के विरुद्ध सख्त प्रहार

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन-जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के माध्यम से युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार, तस्करी और मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला में शामिल आरोपियों के विरुद्ध भी लगातार सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विगत तीन दिनों में विभिन्न जिलों में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 82 लाख रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ एवं तस्करी में प्रयुक्त वाहन जब्त किए।

डीजीपी ने भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त अधिकारियों को लगाई रैंक

भोपाल। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा (चयन सूची-2025) के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के सात अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (मध्यप्रदेश कैडर) में नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय, भोपाल में अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा की रैंक लगाई।

इस दौरान डीजीपी श्री कैलाश मकवाणा ने सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि आपकी समर्पित एवं निष्ठापूर्ण सेवा का प्रतिफल है। प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था बरकरार रखने में

आपने उत्कृष्ट कार्य किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आप प्रदेश की प्रगति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देंगे। आप अपनी कार्यप्रणाली एवं व्यवहार को ऐसा रखें कि वह अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बने। उन्होंने कहा कि समय पर योग्य अधिकारियों को अवसर प्रदान किया जाना सदैव सरकार की प्राथमिकता रही है, जिसका परिपालन करते हुए मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया है। डीजीपी श्री मकवाणा ने पुलिस मुख्यालय में श्रीमती निमिषा पाण्डेय, श्री मलय जैन, श्री अमित सक्सेना, श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, श्रीमती सुमन गुर्जर, श्री सब्यसाची सराफ तथा श्री समर वर्मा को भारतीय पुलिस सेवा की रैंक लगाई। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा (चयन सूची-2025) के इन अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हुए मध्यप्रदेश कैडर आवंटित किया गया है।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।